राजग में फूट, विपक्ष एकजुट... | सिंदरी पर कितनी राजनीति होगी भाई... | बिहार की पॉलिटिकल पिच पर छाये तेजस्वी...

मूल्य : ₹ 20
जून, 2018

पूर्वी भारत की पहली राजनीतिक पत्रिका

राजनीति गुरु

सियासत जारी है...

12
सुदेश हारे या हराये गये

17
दिनेश उरांव के कटाक्ष का मतलब

राजद और भाजपा को साथ-साथ साधकर झारखंड की इस दबंग पूर्व मुख्य सचिव ने घाघ राजनेताओं को भी पानी पिला दिया

सियासत की सट्टेबाज

राजबाला

सफलता की मिठास के आगे सब फीका है.
Congratulations
to
ELITEANS...
Amardeep Jha Gautam
Director
Rocked in 2017
JEE-main : 172
JEE-Advanced : 36
NEET (PMT) :63
IIT-JEE में लहराया परचम
For Scholarship
Take
ELITE
Talent-Support Examination
(ETSE)
Scholarship on the basis of Board - Result
Year 2015
32 PMT (Medical)
27 JEE- Advanced
156 JEE-Main
Year 2016
54 NEET (PMT)
30 JEE - Advanced
162 JEE - Main
Year 2017
63 NEET (PMT)
36 JEE - Advanced
172 JEE - Main
एलिट इंस्टीट्यूट के 63 विद्यार्थी नीट में सफल
पटना के एलिट इंस्टीट्यूट के 172 स्टूडेंट्स हुए सफल
सीबीआई के पूर्व निदेशक ने एलिट के विद्यार्थियों को बताए सफलता के गुर
जेइइ एडवांस परीक्षा में एलिट इंस्टीट्यूट के 30 छात्र सफल
एलिट इंस्टीट्यूट के 162 छात्रों ने परचम लहराया
एलिट इंस्टिट्यूट लेकर आया बेहतरीन इंटीग्रेटेड कोर्स
निकिता को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
ADMISSION - OPEN
Feel the True Essence of Wisdom.
Feel the Innovation in Education...
ELITE Institute
IIT-JEE/PMT/Found. [XI & XII]
An ISO 9001 : 2008 Certified Institute
1st Floor & 4th Floor, Jagdamba Tower,
Sahdeo Mahto Marg, BORING ROAD, PATNA-1
Contact No. : 9835441003 / 9939665084 / 8294186306.
Help-Line : 0612-3054153
Website : www.elite-edu.org
www.facebook.com/eliteiitjee

पूर्वी भारत की पहली राजनीतिक पत्रिका

राजनीति गुरु

सियासत जारी है...

जून, 2018

www.rajneetiguru.com

संपादक
राघवेंद्र

कार्यकारी संपादक
उदय चौहान

राजनीतिक संपादक
शैलेश तिवारी

समन्वय संपादक
मनोज कुमार सिंह

प्रबंध संपादक
मुकेश मिश्रा

सहायक संपादक
कुणाल कुमार

ब्यूरो प्रमुख
मृत्युंजय श्रीवास्तव
रंजीत झा (संथालपरगना)

ऑनलाइन एडिटर
राजीव कुमार

प्रमुख संवाददाता
श्रीधर वत्स

सीनियर रिपोर्टर
रतन कुमार, कौशलेंद्र, कुमुद रंजन

क्रियेटिव हेड
सुभाष

असिस्टेंट मैनेजर (मार्केटिंग)
पंकज मिश्रा (पटना)

इस अंक के कंटेंट से संबंधित प्रतिक्रिया और अपने सुझाव इमेल के जरिये भेज सकते हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव का इंतजार रहेगा।

contact@rajneetiguru.com

बिहार कार्यालय
जी-603, मुंडेश्वरी इनक्लेव,
आशियाना रोड, पटना

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक-प्रकाशक
राघवेंद्र द्वारा कोहीनूर प्रिंटर्स बरियातु, रांची, से मुद्रित एवं 202, सरोजनी उमा, हरिहर सिंह रोड मोरहाबादी, रांची से प्रकाशित

सभी कानूनी मामले रांची के सक्षम न्यायालय द्वारा निपटाये जायेंगे।

आरएनआई नंबर आवेदित

अपनी बात

राजनीति का किस्मत कनेक्शन

आप जैसे सजग पाठकों की ताकत पर हमारी टीम ने हर अंक को राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर आधारित विशेषांक बनाने की कोशिश की है. हमारी कोशिश है कि राजनीतिक गुरु एक विश्वसनीय पत्रकारिता की धारा बने, जो तटस्थ रूप से तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों का मूल्यांकन करे.

आपने राजनीतिक गुरु के प्रत्येक अंक को हाथों-हाथ लिया है, और आपके संबल से हम इतनी दूरी तय कर पाए हैं.

इस अंक में झारखंड की बहुचर्चित नौकरशाह राजबाला वर्मा की सियासी कथाओं से आपको परिचित कराएंगे. आप इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं. आपने इस अधिकारी की वजह से बिहार और झारखंड में कई सियासी तूफान उठते देखे हैं. हम लोगों ने इसे ही समझने की कोशिश की है. इसके अलावा सिल्ली और गोमिया उपचुनाव के नतीजे का विश्लेषण और झारखंड में आगे की राजनीति की समीक्षा की गई है. विधानसभा अध्यक्ष के कटाक्ष भरे संकेत और संथाल परगना की राजनीति भी हमारे विश्लेषण के केंद्र में है.

बिहार की राजनीति के नौजवान चेहरों से भी हम आपको परिचित कराएंगे, साथ ही अपने दम पर सियासत में मुकाम बना रही कुछ महिला चेहरों की भी चर्चा करेंगे.

सिंदरी खाद कारखाने की नींव रखने पिछले दिनों प्रधानमंत्री झारखंड आये थे. हमने विधानसभा के रिकॉर्डों से ढूंढ निकाला कि भाजपा सरकार के वक्त ही इसे बंद करने का भी फैसला किया गया था और तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारों ने इसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की.

कुल मिलाकर यह अंक भी झारखंड और बिहार की सियासत को समग्रता में देखने की हमारी विनम्र कोशिश है .उम्मीद है हमेशा की तरह आपके सहयोग और सुझाव दोनों ही हमें प्राप्त होंगे .

धन्यवाद...
राघवेंद्र

इस अंक में

पूर्वी भारत की पहली राजनीतिक पत्रिका

राजनीति गुरु

सियासत जारी है...

सत्ता समीकरण की राजरानी राजबाला

कवर स्टोरी

पेज >> 5-8

सिंदरी पर सियासत

भाजपा सरकार ने ही बंद कराया था कारखाना

खास खबर

पेज >> 13-16

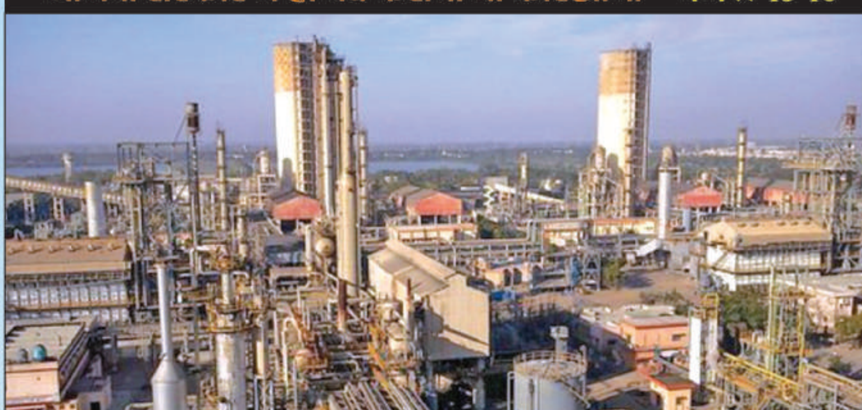

भविष्य के संकेत

पेज >> 9-12

हल्ला बोल

पेज >> 17-19

नजरिया

पेज >> 20-22

चेहरे की लड़ाई

पेज >> 38-40

41

पॉलिटिकल पिच पर छा गए

तेजस्वी

विपक्ष का काउंट डाउन

44

बोरियो में लड़ाई बड़ी कठिन है भाई!

एसेंबली लाइव

सत्ता और समीकरण की खिलाड़ी राजबाला !

आखिर कौन हैं राजबाला वर्मा ! जब लालू प्रसाद पहली बार चारा घोटाले में जेल गए तो बेउर जेल के सामने रोती हुई इनकी तस्वीर पटना के कुछ अखबारों में छपी थी। तब ये पटना की डीएम थीं, लालू प्रसाद की खासमखास। जब झारखण्ड में रहीं तो यहां की सत्ता का निर्बाध संचालन। आखिर क्या है इनका परिचय ! क्या छुपा है इनके अतीत में। ये सियासत की बाजीगर हैं या नौकरशाही की। झारखण्ड की पूर्व मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा आज किसी औपचारिक पद पर नहीं हैं लेकिन झारखण्ड की सत्ता अभी भी इनके इशारों पर कदमताल करती है। जब सत्ता की महारानी थी, तो झारखण्ड के कई मंत्री इनसे मिलने के लिए अर्जियां भिजवाते थे। जब सत्ता में नहीं हैं तब भी एचइसी के इनके क्वार्टर में इनके भक्तों और शागिर्दों की भीड़ जुटती है। राजद और भाजपा दोनों ही दलों को साधने का आखिर कौन सा फार्मूला है इनके पास। दो विपरीत ध्रुवों पर चलने वाले सियासी समूह को कैसे इन्होंने अपने इशारे पर नचाया ! क्या राजबाला राजनीति के मैदान में उतरेंगी ! **राघवेंद्र का नजरिया...**

झारखण्ड में नेताओं और अधिकारियों का एक बड़ा समूह इनसे नफरत करता है, इन्हें तानाशाह, महाभ्रष्ट, हिटलर और ना जाने क्या-क्या कहता है, इनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी भाजपा के गलियारे में सुनी जा सकती है, लेकिन इन बातों से बेफिक्र राजबाला अपने भाजपाई और पूर्व आईएएस पति जेबी तुबिद के साथ रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। यह ताकतवर महिला मुख्यमंत्री की सलाहकार बनने की जुगत में दुबारा जुट गयी है। इनके मुख्य सचिव पद से हटने के बाद भी सलाहकार बनने की इनकी फाइल बढ़ी थी लेकिन सरयू राय और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं के विरोध के कारण मुख्यमंत्री को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। राज्य सरकार के मंत्री सरयू राय ने तो उन्हें सार्वजनिक रूप से विवादास्पद अधिकारी बताया। उन्होंने 6 मार्च 2018 की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री सचिवालय से संबद्ध जनसम्पर्क विभाग की टीम पर ही सवाल उठा दिया।

हुआ यूं कि कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विवादस्पद उप निदेशक अजय नाथ झा (राजबाला वर्मा के पति जेबी तुबिद और अजय नाथ झा ने नेतरहाट स्कूल से ही पढ़ाई की है) ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के अंत में कैबिनेट के अन्यान्य शीर्षक को उल्लेखित करते हुए लिखा कि राजबाला वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, 1983 बैच की अधिकारी जो 35 वर्षों की सेवा के बाद 28 फरवरी 2018 को सेवानिवृत हुईं, को एक कुशल एवं दक्ष प्रशासक के रूप में तथा मुख्य सचिव के पद पर सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिये मंत्रिपरिषद ने आभार प्रकट किया तथा उन्हें भविष्य के लिये शुभकामनायें दी।

राजबाला वर्मा की इस झूठ से आग बबूला हुए सरयू राय ने तब मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पत्र लिखकर कहा कि जिस अधिकारी का सेवा कार्यकाल अप्रत्याशित रूप से विवादास्पद रहा है, जिसके प्रशासनिक आचरण में संवेदनशीलता का अभाव रहा है, जिसके विरूद्ध नियम-कानून की दंडनीय अवहेलना जानबूझकर करने का पुष्ट प्रमाण है, एकीकृत बिहार के समय भ्रष्ट एवं घोटाला के आरोपी शीर्ष पदधारी राजनीतिज्ञों के प्रति जिसका समर्पण भाव जगजाहिर है,

जिसने पशुपालन घोटाला के विरूद्ध आंदोलनरत भाजपा कार्यकर्ताओं को उस समय प्रताड़ित किया है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद पशुपालन घोटाला के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में बाधा डाली है जिसके कारण सीबीआई को सेना से मदद की गुहार करनी पड़ी, घोटाला के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर पटना के बेउर जेल भेज दिया गया तो जिसने संवैधानिक एवं प्रशासनिक मर्यादा की अवहेलना कर अभियुक्त की सहानुभूति में बेउर जेल गेट पर करूण कंदन किया, चुनाव आयोग ने गया में जिलाधिकारी के रूप में जिसके आचरण के विरूद्ध सख्त टिप्पणी की है एवं जिसे भविष्य में चुनाव कार्य में भाग लेने से मना किया है, मुख्य सचिव रहते जिसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के निर्देश के उलट प्रशासनिक निर्देश जारी किया है जिस कारण हजारों लाभुकों के राशन कार्ड रद्द हो गए।

राजबाला वर्मा के मुख्य सचिव के पद से हटने के बाद भी सलाहकार बनने की इनकी फाइल बढ़ी थी लेकिन सरयू राय और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं के विरोध के कारण मुख्यमंत्री को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

झारखण्ड सरकार के मंत्री सरयू राय के दावे में दम है। चारा घोटाले की जांच से जुड़े रहे सीबीआई के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात की तस्दीक करते हैं

कल्याण मंत्री की अवहेलना कर जिसने संचिका पर मनमाना आदेश दिया है, जिसका जिक्र सितंबर 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष होने पर मंत्री ने यह आदेश रद्द किया,पथों के चौड़ीकरण (विशेषकर गुआ-सलाई-पथ का चौड़ीकरण) के लिये जिसने फर्जी सर्वेक्षण पर मुहर लगाया है और संबंधित नियम-कानून की अनदेखी किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने जिसके विरूद्ध 'इरादों में ईमानदार नहीं होने' की टिप्पणी की है और कहा है कि संवेदक भी इस बेईमानी का हिस्सा है, जिसके कार्यकाल में कार्य विभागों के ठेकों को मैनेज करने के दंडित किये जाने योग्य आरोपी अभियंताओं-अफसरों को प्रश्रय मिला है एवं लोकनिधि का अपव्यय करनेवाली माफियानुमा कार्यसंस्कृति को बढ़ावा मिला है, ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है, पुलिस और प्रशासन का शीर्षस्तर खेमेबाजी का शिकार हो गया है, प्रशासन का डिलीवरी सिस्टम पंगु हो गया है।

वैसे अधिकारी की सेवानिवृति पर उसके प्रति उपर्युक्त शब्दों में मंत्रिपरिषद द्वारा उसके संपूर्ण कार्यकाल के लिये सराहना करने एवं आभार प्रदिर्शत करने का समाचार प्रकाशित होने से जनमानस में मंत्रिपरिषद की छवि धूमिल हुई है। ऐसा करने वाले और उन्हें ऐसा करने का आदेश देने वाले निश्चित रूप से दंड के भागी हैं।

झारखण्ड सरकार के मंत्री सरयू राय के दावे में दम है। चारा घोटाले की जांच से जुड़े रहे सीबीआई के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात की तस्दीक करते हैं। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब आरसी 20/96 में लालू प्रसाद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, तब राजबाला पटना की जिलाधिकारी थी। सीबीआई को रैपिड एक्शन फोर्स मिला हुआ था। राजबाला ने इसके कमान्डेंट को स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि बिना उनकी इजाजत के यह फोर्स कोई मूवमेंट नहीं करेगा। उस वक्त बिहार के डीजीपी एसके सक्सेना थे, वो भी सीबीआई के अधिकारियों के फोन नहीं उठा रहे थे। बिहार के मुख्य सचिव भी जांच एजेंसी के अधिकारियों का कॉल नहीं उठा रहे थे। फोन ड्यूटी पर मौजूद शख्स कह रहा था कि साहेब नहीं हैं।

पूरी राज्य मशीनरी लालू की गिरफ्तारी को टालने में जुटी थी। राजबाला वर्मा बार- बार मुख्यमंत्री आवास आ-जा रही थीं और सुरक्षाकर्मियों को किसी को अंदर नहीं आने जैसी हिदायतें दे रही थीं। कानून की रखवाली करने की बजाय राजबाला वर्मा कानून को ही कमजोर कर रही थीं। इसके बाद ही सीबीआई ने तब सेना की मदद के लिए दानापुर छावनी के ब्रिगेडियर नौटियाल से संपर्क किया। सीबीआई के तब के एसपी कौमुदी उस वक्त की परेशानियों की बातें ऑफ द रिकॉर्ड अपने सहयोगियों से साझा करते हैं। चाईबासा की जिलाधिकारी रहने के दौरान भी राजबाला ने घोटाले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसके लिए केन्द्रीय जांच एजेंसी ने इनके लिए माइनर पेनाल्टी का रिकमेन्डेशन किया था। बात सामने आयी तो विधानसभा में बबाल हुआ। राज्य सरकार ने आखिरकार इनसे स्पष्टीकरण मांगा और माइनर पेनाल्टी की सजा दी।

ईमानदारी के कसीदे पढ़ने वाले मुख्यमंत्री ने एक ईमानदार अधिकारी की जगह एक दागी अधिकारी, राजबाला को चुना। यह भाजपा की बदलाव की राजनीति में पलीता लगाने की कोशिश थी।

यहां एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। झारखण्ड के मुख्यमंत्री के सामने दो अधिकारी थे, चारा घोटाले की आरोपी (दंड सांकेतिक ही सही लेकिन आरोप तो सही साबित हुआ) राजबाला वर्मा और चारा घोटाले को प्रकाश में लाने वाले अमित खरे। लेकिन ईमानदारी के कसीदे पढ़ने वाले मुख्यमंत्री जी ने एक ईमानदार अधिकारी की जगह एक दागी अधिकारी को चुना।

हाल के महीनों में राजबाला वर्मा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चर्चे सत्ता के गलियारे में लगातार सुने जाते रहे। कभी कोडरमा तो कभी पलामू लोकसभा सीट को लेकर उनकी चर्चा होती रही। जब भी कभी वह गुमला और बिशनपुर इलाके में गईं तो यह चर्चा भी तेज हो गई कि राजबाला वर्मा यहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं ।

यह भाजपा की बदलाव की राजनीति में पलीता लगाने की कोशिश थी।

झारखण्ड में पथ निर्माण सचिव और बाद में मुख्य सचिव रहने के दौरान राजबाला वर्मा पर आरोप है कि पथ निर्माण विभाग को इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह यूज किया। सर्वेक्षण से लेकर ठेकेदारों के चयन तक में भारी गड़बड़ी की गयी। अपने कुछ कृपापात्र ठेकेदारों पर मैडम की कृपा ऐसी बरसी कि सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। पथ निर्माण विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि 8-10 कम्पनी को मैडम का वरदहस्त मिला हुआ था। इन कम्पनियों के बारे में नीचे तक स्पष्ट संकेत थे। इन कम्पनियों के प्रतिद्वंदियों को टेक्निकल बीड में ही छांट दिया जाता था।

हाल के महीनों में राजबाला वर्मा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चर्चे सत्ता के गलियारे में लगातार सुने जाते रहे। कभी कोडरमा तो कभी पलामू लोकसभा सीट को लेकर उनकी चर्चा होती रही। जब भी कभी वह गुमला और बिशनपुर इलाके में गईं तो यह चर्चा भी तेज हो गई कि राजबाला वर्मा यहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। अब वह कहां - कहां से चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा लड़ेंगी या विधानसभा, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है , लेकिन उनके करीबी लोग बताते हैं कि राजनीतिक महत्वकांक्षा के रथ पर सवार श्रीमती वर्मा देर-सवेर झारखंड की सियासत का कद्दावर चेहरा होंगी। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा उनकी पहली पसंद है। उनके पति और पूर्व नौकरशाह जे बी तुबिद चाईबासा से चुनाव लड़ चुके हैं, लड़कर हार चुके हैं । अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो क्या आने वाले दिनों में झारखंड के इस नौकरशाह दंपत्ति को लोग एक साथ राजनीति के मंच पर देखेंगे। संभावना और संकेत तो यही कह रहे हैं। हालांकि नौकरशाही और राजनीति में राजबाला के कटु आलोचकों की कमी नहीं है।

ऐसे लोगों का कहना है कि राजबाला वर्मा के कामकाज का जो तरीका रहा है, उससे तो यही लगता है कि वह बैक डोर पॉलिटिक्स करेंगी। शायद ऐसे लोगों का संकेत राज्यसभा की तरफ है। भाजपा के अंदर अर्जुन मुंडा, सरयू राय और भी कई मंत्री विधायक तथा आरएसएस का एक बड़ा तबका राजबाला वर्मा का नाम सुनते ही नाक -भौं सिकोड़ने लगता है। ऐसे में उनके टिकट की गारंटी आसान नहीं दिखती। ऐसे ही सियासी जोड़-घटाव में लगी राजबाला वर्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने की रेस में तेजी से सामने आई हैं। यह भी उनका राजनीतिक कौशल ही है कि एक बार बनते-बनते बात बिगड़ जाने के बाद भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। वैसे ही प्रयासों को तो राजनीति कहते हैं। अब देखिए, आगे इनकी राजनीति क्या रंग लाती है।

विपक्ष एकजुट, एनडीए में फूट

झारखंड में एकजुट विपक्ष क्या राजग का रास्ता रोक सकता है। ऐसा उपचुनाव में हुआ भी। एनडीए की हार तो हुई ही। उसकी साख भी दांव पर लग गई। इस चुनाव परिणाम ने एक साथ ऐसे कई पुराने मुद्दों को अचानक उभार दिया है जो आजसू-बीजेपी के बीच पिछले साढ़े तीन सालों से अंदर ही अंदर किसी तरह ढंककर रखे जा रहे थे। एनडीए पार्टनर आजसू सरकार के कई फैसलों का विरोध करता रहा है।

झारखंड के दो विधानसभा सीटों सिल्ली और गोमिया में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दोनों सीटों पर झामुमो का कब्जा बरकरार रहा। सिल्ली से झामुमो प्रत्याशी सीमा महतो ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को 13,510 वोटों से हराया जबकि गोमिया से झामुमो प्रत्याशी बबिता देवी ने आजसू उम्मीदवार लंबोदर महतो को 1341 वोटों से पटकनी दी। झामुमो की इस जीत और बीजेपी, आजसू की हार के पीछे की जो कारण हैं वह धीरे-धीरे सतह पर आने लगे हैं।

झामुमो नेता हेमंत के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष के हाथों मिली करारी हार से तिलमिलाए एनडीए में पहले दिन ही बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी और आजसू के नेता सामने आए और एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि हार के खलनायक कोई और नहीं उनका सहयोगी दल ही है। ऐसा लगा कि दोनों दलों को पहले से ही पता था कि उनका पार्टनर ही जीत में रोड़ा अटका सकता है। उनका रास्ता रोक सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। एनडीए की हार तो हुई ही। उसकी साख भी दांव पर लग गई। इस चुनाव परिणाम ने एक साथ ऐसे कई पुराने मुद्दों अचानक उभार दिए हैं जो आजसू- बीजेपी के बीच पिछले साढ़े तीन सालों से अंदर ही अंदर किसी तरह ढंककर रखे जा रहे थे। एनडीए पार्टनर आजसू सरकार के कई फैसलों का विरोध तो करता था, लेकिन सत्ता के साथ था तो जनता ने उस विरोध को पॉलिटिकल स्टंट से अधिक और कुछ भी नहीं समझा। विपक्ष तो यहां तक कहता रहा कि सत्ता में रहकर सुदेश महतो का यह विरोध सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं। कुछ हद तक आम आवाम में भी ये धारणा उस समय बनती दिखी जब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएनटी- एसपीटी संशोधन विधेयक, स्थानीय नीति में संशोधन को मंजूरी दी। पूरा विपक्ष इस संशोधन के खिलाफ था, सड़क पर था, सदन में भी इस विधेयक का जोरदार विरोध होता रहा था। विपक्ष के विरोध के कारण पूरा बजट सत्र बाधित रहा। कई विधायकों को उनके विरोध करने के कारण सदन के सत्र से निलंबित तक कर दिया गया। पर आजसू सरकार के साथ रही उसने इसका सदन में विरोध नहीं किया, केवल सड़क पर आजसू के विरोध के स्वर सुनायी पड़े।

इस मुद्दे को लेकर सुदेश महतो और उनकी पार्टी ने सदन के बाहर खूब आवाज उठायी लेकिन उनके इस विरोध को सियासी पैंतरा समझा गया। अपने इस विरोध से न तो आजसू सरकार पर दबाव बना पाया और नहीं जनता को यह समझा पाया कि वह उसकी हितैषी पार्टी है। हालांकि, इस मुद्दे पर बाद में विपक्षी दलों के घेरने के बाद जब भाजपा के ही कई विधायकों ने विरोध के सुर तेज कर दिए तो आखिरकार सरकार बैकफुट पर आयी और संशोधन को वापस लेना पड़ा। कुल मिलाकर यह हुआ कि विपक्ष ने तो इसे अपनी जीत बताया लेकिन आजसू ऐसा नहीं कर सकी और वह सरकार के साथ ही खड़ी दिखी। उपचुनाव में हार के बाद सुदेश महतो के बयान पर गौर करें तो इस बात की तस्दीक होती है कि वे नहीं चाहते थे कि सरकार कोई भी ऐसा फैसला लेकर आए जिससे सहयोगी दल होने के नाते उनकी सियासी जमीन पर खतरा पैदा हो।

> आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सरकार की जनविरोधी नीतियों का लगातार विरोध किया पर सरकार ने उनके विरोध को सिर्फ सियासी हमले के तौर पर लिया।

चारा घोटाला के केस में लालू के लगातार रांची दौरे से राज्य की विपक्षी पार्टियों को उनके साथ बैठने और सूबे में सियासी रणनीति बनाने का मौका मिला जिससे धीरे-धीरे विपक्ष का एक साथ बैठना शुरू हुआ।

इस बात का मलाल सिल्ली की हार के बाद सुदेश महतो के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। उन्होंने कहा भी कि सरकार ने विपक्ष को मौका दिया, सीएनटी-एसपीटी, जमीन अधिग्रहण चुनाव में मुद्दे बने। इससे बीजेपी और आजसू दोनों को नुकसान हुआ। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि सरकार से वह कई बार ये बात कह चुके हैं कि नीतिगत फैसले सामूहिक निर्णय से लिए जाएं, सभी दलों को विश्वास में लेकर फैसला हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसका फायदा विपक्षी दलों ने उठाया और जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया। ये बात सच है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कई बार सार्वजनिक तौर पर सरकार के फैसलों के खिलाफ बयान दिए हैं। लेकिन उनका असर सरकार पर नहीं हुआ है यह भी एक तथ्य है। अब जब एक साल के अंदर राज्य में लोकसभा और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो आजसू सुप्रीमो को लगने लगा है कि उनकी सियासी जमीन खिसकती जा रही है। इसलिए उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के सहयोग और गठबंधन पर पुर्निवचार किया जाएगा। पार्टी हार के कारणों और एनडीए में बने रहने का ठोस मूल्यांकन करेगी।

बीजेपी और आजसू के बीच आनेवाले दिनों में तालमेल रहेगा या नहीं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों में अंदर खाने यह बात रखी जा रही है कि ऐसे समय में जब विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े होते जा रहे हैं।

इन सब के बीच बीजेपी और आजसू के बीच आनेवाले दिनों में तालमेल रहेगा या नहीं इस पर चर्चा शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों में अंदर खाने यह बात रखी जा रही है कि ऐसे समय में जब विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े होते जा रहे हैं। कुछ हद तक यह बात भी सही लगती है कि जब विपक्ष के कई दल एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं तो एनडीए के दो प्रमुख दल क्यों नहीं। देखा जाय तो विपक्षी एकजुटता की कवायद काफी पहले शुरू हो चुकी है।

इसका पहला टेस्ट राज्यसभा चुनाव के दौरान ही हो चुका था। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार रणनीति बनाकर विपक्ष मैदान में उतरा उसने सत्तापक्ष को किसी भी प्रकार के दांव-पेंच को कामयाब नहीं होने दिया और अंततः कांग्रेस के उम्मीदवार धीरज साहू की जीत हुई। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो विपक्षी एकता इतनी आसान नहीं थी जितना अभी दिखाई दे रही है। इसके लिए कई महीनों तक और कई दौर की बैठकें हुई हैं, तब जाकर इसे अमलीजामा पहनाया जा सका।

कहा जाता है कि इसके पीछे चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की अहम भूमिका रही है। चारा घोटाला के केस में उनके लगातार रांची दौरे से राज्य की विपक्षी पार्टियों को उनके साथ बैठने और सूबे में सियासी रणनीति बनाने का मौका मिला जिससे धीरे-धीरे विपक्ष का एक साथ बैठना शुरू हुआ। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, झाविमो प्रमुख बाबू लाल मरांडी, कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार, सुबोधकांत सहाय, सुखदेव भगत सहित अन्य सभी बड़े नेता लगातार संपर्क में रहे। इस बीच कांग्रेस और झामुमो के बीच कई दौर की बातचीत हुई और अंत में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष एक फॉर्मूला तय हुआ कि राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार को झामुमो सपोर्ट करेगा जबकि इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़े जाएंगे।

विपक्ष अब इस बात को भलीभांति समझ चुका है कि भाजपा या एनडीए को हराने के लिए आपसी मतभेद को भूलाना होगा। एक-दूसरे पर छींटाकशी और आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय भाजपा के खिलाफ संगठित होना होगा।

विपक्ष इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है हालांकि बीच में निकाय चुनाव के दौरान सभी दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पर उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि निकाय चुनाव में महागठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, इसीलिए कांग्रेस, झामुमो, राजद, झाविमो, लेफ्ट सारे दल अलग-अलग चुनाव में उतरे। निकाय चुनाव में भी कांग्रेस, झामुमो ने ग्रामीण इलाकों में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया और अपनी जोरदार मौजूदगी ने भाजपा को यह एहसास करा दिया कि आने वाले समय में उसकी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। बहरहाल, भाजपा को जिस प्रकार की जीत निकाय चुनाव में मिली, उससे पार्टी के नेताओं को यह जरूर लगने लगा कि भाजपा के सामने विपक्ष टिक नहीं पाएगा। पार्टी के कई नेताओं ने तो सरेआम यह कह भी दिया कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से आम आवाम खुश है, भाजपा की लहर अभी भी कायम है। लोगों से सीधा संपर्क कर रहे थे। भाजपा के सभी बड़े नेताओं को उम्मीद थी कि गोमिया पर जीत उनकी पार्टी के उम्मीदवार की ही होगी। उधर, 25 मई को सिंदरी में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र के दौरे से भी यह कहा जा रहा था कि वोटरों पर इसका कुछ न कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन तमाम दांव-पेंच को जनता ने खारिज कर दिया और झामुमो प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज पहना दिया।

ऐसे समय में जब सरकार का पूरा अमला गोमिया में दिन-रात कैंप कर रहा हो, विपक्ष के लिए जीत की राह उतनी आसान नहीं थी। इसके लिए उन्हें भी खूब पसीना बहाना पड़ा। इन दोनों सीटों पर पूरा विपक्ष गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहा था। कांग्रेस, राजद, झाविमो और लेफ्ट के नेता भी लगातार मतदाताओं से मिल रहे थे उन्हें अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार कर रहे थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा वर्तमान दौर में झारखंड में पहली बार हुआ है कि विपक्षी दलों के सभी प्रमुख एक साथ मंच शेयर कर रहे हों और गांव-गांव जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हों। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष अब इस बात को भलीभांति समझ चुका है कि भाजपा या एनडीए को हराने के लिए आपसी मतभेद को भूलाना होगा। एक-दूसरे पर छींटाकशी और आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय भाजपा के खिलाफ संगठित होना होगा।

विपक्षी एकजुटता से भाजपा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, यह भ्रम एक महीने में ही टूट गया। उपचुनाव में जिस प्रकार विपक्षी दलों ने एक मंच पर खड़ा होकर अपनी ताकत दिखायी उसने भाजपा के विकास के दंभ की सारी हवा निकाल दी। गोमिया में पार्टी प्रत्याशी माधवलाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे। जबकि अपने उम्मीदवार को जीताने के लिए प्रदेश भाजपा की पूरी टीम क्षेत्र में कैंप कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास इस गोमिया का लगातार दौरा कर रहे थे। राजनीति में दल या नेता तकनीकी तौर पर हारते जरुर हैं, लेकिन असल में हारते हैं समीकरण।

राजनीति में दल या नेता तकनीकी तौर पर हारते जरुर हैं, लेकिन असल में हारते हैं समीकरण। और इस बार यह समीकरण पूरी तरह भाजपा मित्रमंडल दलों के खिलाफ था।

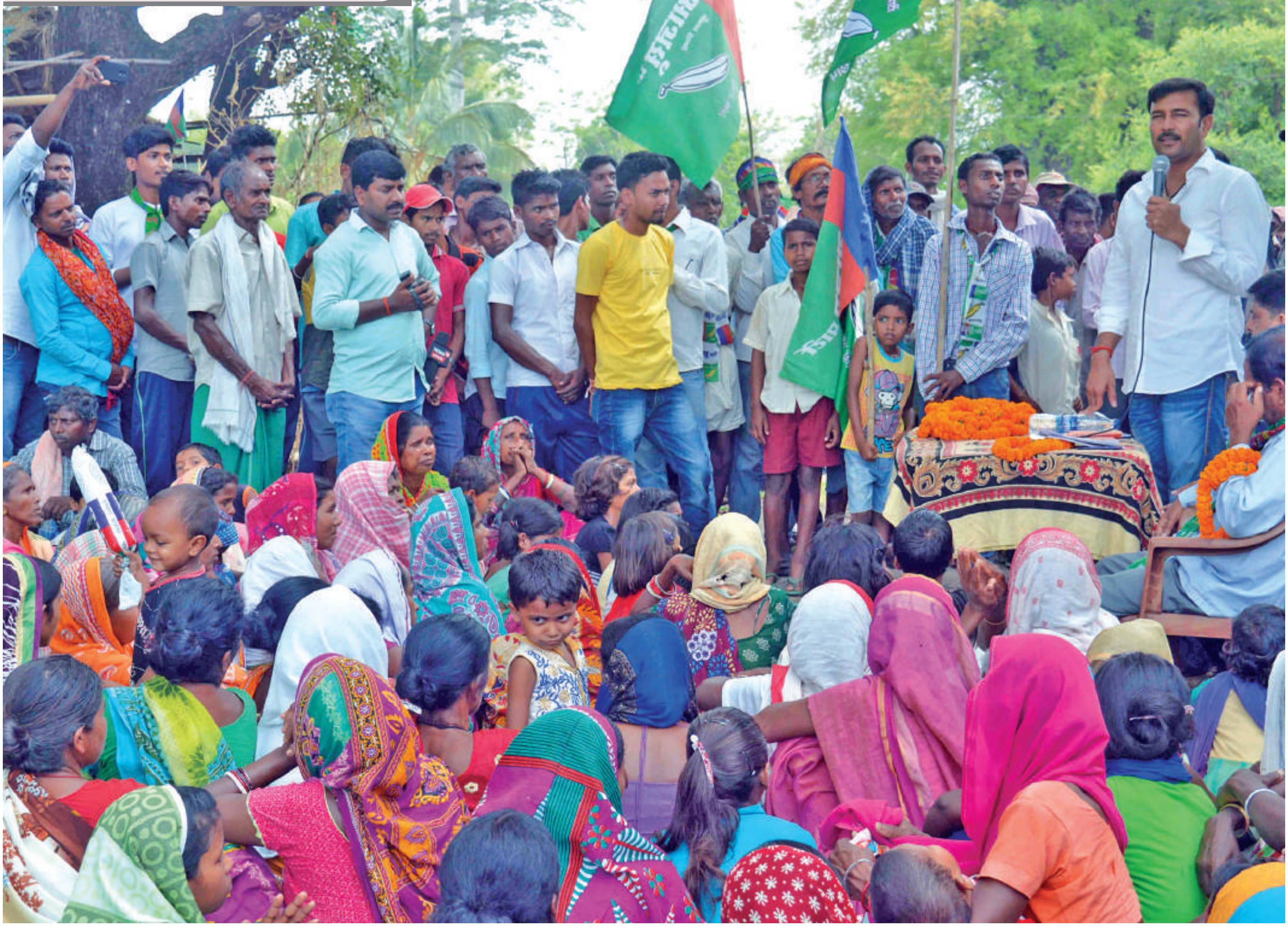

सुदेश हारे, लेकिन आजसू का वोट बढ़ा

और इस बार यह समीकरण पूरी तरह भाजपा मित्रमंडल दलों के खिलाफ था। राज्य सरकार की स्थानीय नीति और सीएनटी तथा एसपीटी में संशोधन की कोशिशों की वजह से नाराज लोगों ने भाजपा को तो हराया ही, आजसू को भी एनडीए में होने की कीमत चुकानी पड़ी।

इसी का नतीजा है कि सिल्ली में 11.5 प्रतिशत वोट वृद्धि और गोमिया में 35 प्रतिशत वोट बढ़ने के बाद भी आजसू ने दोनों सीटें गंवा दी। लेकिन क्या इस हार के बाद आजसू पार्टी और इसके प्रमुख सुदेश महतो को सियासी तौर पर चूका हुआ मान लेना उचित है! बिलकुल नहीं! सुदेश महतो आज भी झारखण्ड की पिछड़ी राजनीति के चैंपियन हैं। आजसू और अन्य दलों के वोटों का तुलनात्मक अध्ययन इस बात को और पुष्ट करता है।

सबसे पहले बात सिल्ली की। 2014 में महागठबंधन उम्मीदवार को यहां 87000 वोट मिले थे तथा आजसू को तब मात्र 50000 मत मिले थे। 2018 में आजसू बढ़कर 63500 तक पहुंच गया जबकि महागठबंधन उम्मीदवार को मिले 77000 मत। इसी तरह गोमिया में 2009 में आजसू मिले थे 24000 मत, जबकि 2018 में मिले 59000 मत। भाजपा को 2014 में मिले थे 56000 वोट, इस बार 2018 में मिले 41000 वोट। 2014 में झामुमो को गोमिया में मिले थे 94000 वोट जबकि 2018 में मिले मात्र 61000। इस तरह देखा जाये तो केवल आजसू के वोट बढ़े हैं, जबकि भाजपा और झामुमो के वोट घटे हैं।

ये आंकड़े इस बात की भी गवाही देते हैं कि आजसू का बढ़ता वोट बैंक पिछड़ों में इस पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है। स्थानीय नीति की विसंगतियों पर आजसू ने सड़क से सदन तक विरोध किया था और इसे झारखण्ड के स्थानीय लोगों के लिए आत्मघाती कदम बताया था। इतने के बाद भी सिल्ली में भाजपा नेताओं ने सुदेश महतो की राह में रोड़े अटकाए, गठबंधन धर्म के खिलाफ उन्हें हराने में ऊर्जा लगाते रहे, फिर भी आजसू के वोट बैंक में इजाफे के बाद भी आखिर किसी नेता को खारिज और चूका हुआ कैसे माना जा सकता है।

इन दोनों उप चुनावों के नतीजे झारखण्ड की गठबंधन राजनीति को आनेवाले दिनों में गहरे प्रभावित करेंगे। भाजपा और आजसू के बीच की दूरी बढ़ सकती है। झामुमो अभी अपनी जीत के जश्न में सभी गैर गठबंधन दलों को खत्म होने का सर्टिफिकेट बांट रहा है। हो सकता है झामुमो का अहंकार बाबूलाल की झाविमो को नाराज कर दे और इनके रास्ते फिर अलग-अलग हो जाएं। सियासत में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

आजसू के लिए झारखण्ड का पिच अभी बेहतर है। युवा सुदेश की अगुवाई में आजसू कार्यकर्ता नयी रणनीति बनाकर अभी से जनता के बीच नया राजनीतिक मन्त्र लेकर पहुंचे तो सियासी चमत्कार संभव है। कुछ सवालों के जवाब तो वैसे भी भविष्य के गर्भ में ही छुपे रहते हैं।

सिंदरी पर सियासत

वाजपेयी के वक्त बंदी मनमोहन ने दिया जीवन मोदी ने लिया क्रेडिट

25 मई को सिंदरी में हजारों लोगों की भीड़ मोदी-मोदी के नारे लगा रही थी। बंद पड़े सिंदरी कारखाने के खोलने की तैयारी हो रही थी। मर रहे सिंदरी को नई जिंदगी मिलने वाली थी। पीएम मोदी अपनी सरकार के चार साल पूरा होने पर लोगों को ये बड़ी सौगात सौंप रहे थे,उधर पूरी भाजपा इस बात की क्रेडिट ले रही थी। लेकिन क्या सच यही है! थोड़ा पीछे चलिये, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि सिंदरी खाद कारखाने को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने बीआईएफआर के दायरे से बाहर निकाला था और नया जीवन दिया था। रेवेन्यु बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष बीसएस मीणा और सदस्य जेपी दुआ ने यह फैसला सुनाया था। तत्कालीन सरकार ने अपने कैबिनेट में ये फैसला लिया था कि सिंदरी खाद कारखाने पर जो भी लोन और इंटरेस्ट है उसे माफ किया जाय। इसके बाद बीआईएफआर बेंच ने फैसला दिया कि अब कंपनी अपने जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि वाजपेयी सरकार के वक्त ही इसे बंद करने का फैसला हुआ था। तब राज्य में भाजपा सरकार थी और धनबाद के वर्तमान सांसद पीएन सिह झारखंड के उद्योग मंत्री थे। उस वक्त विधायक अरूप चटर्जी कारखाने को बचाने के लिए सदन में सवाल उठाया था, पर सरकार ने कोई पहल नहीं की थी।

राजनीति गुरु ने झारखंड विधानसभा की उस कार्यवाही को निकाला, जिसमें निरसा के मासस विधायक अरूप चटर्जी ने सिंदरी खाद कारखाने को बचाने के प्रयासों के बारे में राज्य सरकार से जानना चाहा था। तब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे और वर्तमान धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह उद्योग मंत्री। कैसी थी बहस, इसे आप भी जानिये और सिंदरी की सियासत समझिये।

महेन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय मेरा उद्योग विभाग के मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि उनका विभाग इस मामले में थोड़ी गम्भीरता दिखाये।

पशुपति नाथ सिंह (मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महेन्द्र जी का जो गैर सरकारी संकल्प आया है उसको यहां पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रम, राज्य सरकार के उपक्रम के बारे में कहा गया है। मैं इस संबध में कहना चाहता हूं कि उद्योग विभाग इस संबध में कार्य कर रहा है।

महोदय मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि माननीय सदस्य महेद्र जी ने सबके रिभाईवल के लिए सहमति जाहिर की है और साथ ही साथ सरकार से आग्रह किया है कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनको खुलवाने में राज्य सरकार की जितनी भूमिका है, राज्य सरकार उसके लिए कोशिश करेगी। इसी के साथ मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

महेन्द्र प्रसाद सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

गैर सरकारी संकल्प संख्या- 13

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार बालमुचू अनुपस्थित)

अरूप चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक संकल्प था जो छूट गया है इसे ले लिया जाया।

उपाध्यक्ष: ठीक है। पढ़िए।

अरुप चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा अभिस्ताव करती है कि सिन्दरी खाद कारखाना को बंद होने से बचाया जाय।

समरेश सिंह (मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार से संबंधित है। पहले हम लोग यहां से सर्वसम्मति से प्रस्ताव ले लें कि झारखंड विधान- सभा सिन्दरी खाद कारखाना को पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं और झारखंड सरकार इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करे। पूरे झारखंड की जनता इसके साथ है।

गिरिनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से इसको करवा दिया जाय।

पशुपतिनाथ सिंह (मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह जी का जो संकल्प था उसमें भी सिन्दरी खाद कारखाना को बचाने की बात थी। यह बात उस संकल्प में भी निहित है फिर भी ये प्रश्न उठा रहे हैं। एक ही प्रश्न को दो-दो व्यक्ति द्वारा संकल्प के रूप में नहीं लाया जा सकता है। सिन्दरी को बचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार को लिखा भी गया है। हम लोगों ने उसमें सभी बातों को समाहित किया है, साथ में एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कर्मचारी संगठन इस बात को उठाते हैं।

सिन्दरी को बचाने के लिए, यहां राजनेता प्रश्न उठाते हैं लेकिन जो सिन्दरी का प्रबंधन है उसके द्वारा आज तक राज्य सरकार से आग्रह नहीं किया गया है कि हमको इसमें आवश्यक सहयोग किया जाय। हमलोगों ने इस कारखाना को बचाने की दिशा में अपने स्तर से, अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को , केन्द्रीय फर्टिलाईजर मंत्री जी को या अन्य सारे लोगों को इसके संबध में पत्राचार कर के कारवाई की है। इस संबंध में हम लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखलायी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल जाकर प्रधानमंत्री जी आग्रह किया है कि सिन्दरी कारखाना को बचाया जाय । इस बात को लेकर गैर सरकारी संकल्प आना ही नहीं चाहिए था। इसी को लेकर माननीय सदस्य महेंद्र प्रसाद सिंह ने रखा है फिर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। सरकार जागरूक होकर इस दिशा में कार्रवाई कर रही है।

समरेश सिंह (मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिन्दरी को अन्य फर्टिलाईजर यूनिट से अलग कर अगर झारखंड सरकार इसके लिए नहीं प्रयास करेगी तो मुर्दो के साथ जिन्दा आदमी भी उसमें जल जायेंगे इसलिए यह प्रस्ताव आना चाहिए। यह संकल्प नहीं आना चाहिए या आना चाहिए, यह बात दूसरी है।

अरूप चटर्जी और स्व. महेंद्र सिंह ने सिंदरी के सवाल को जोरदार ढंग से उठाया था लेकिन राज्य सरकार ने तब अगर कोशिश की होती तो आज सिंदरी मरता हुआ शहर नहीं होता।

सिन्दरी जैसे मुख्य मुद्दे को झारखंड विधान सभा ने अभी तक पास नहीं किया है। यही सही है कि इसके लिए प्रयास हुआ है, कैबिनेट से पास हुआ है। केवल कैबिनेट से नहीं, यहां भी सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। जब यह अन्य एफसीआई यूनिट से अलग हो जायेगा तब ही हम इसको बचाने में सफल हो सकते हैं। कोई दुर्गापुर से जोड़ने, कोई आन्ध्र प्रदेश से जोड़ने की बात कहता है। इससे यह जिन्दा नहीं होगा।

सिन्दरी यूनिट को अलग करना पड़ेगा और केन्द्र सरकार से मिलकर इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। पूरे ईस्टर्न जोन में यूरिया का प्लांट नहीं है। आज जरूरत महसूस नहीं हो रहा है, एक दिन हमलोग रोयेंगे, इसलिए इसको दूसरे विषय के साथ न जोड़कर सिन्दरी को , जैसे हमलोगों ने एचइसी को प्रायोरिटी दी, सिंदरी सार्वजनिक प्रतिष्ठान की तरह नहीं है, उस दृष्टि से हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सिन्दरी यूनिट को अलग करें। और झारखंड सरकार लीज पर लेकर केन्द्र सरकार से मिल कर सिन्दरी करे पुनर्जीवित करे। प्रबंधन तो बनिया है उसके साथ क्या जोड़ना है?

अरूप चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, इस कारखाने से कम-से कम 15 हजार लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है और आईडी एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी केंद्र संचालित कारखाना या उद्योग अगर स्टेट में बन्द करना चाहे तो उस स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन बहुत जरूरी हो जाती है। यह 25(0)में एक प्रावधान है, तो मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने अगर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली तो स्टेट गवर्नमेंट कारखाना को बंद करने का परमिशन न दे। सेकेन्डली, बीआइएफआर की तो रिपोर्ट है उसने क्लियरली एक चीज कहा है कि केंद्र सरकार इसे चाहती है। कोई टेक्निकल रिपोर्ट इसको बंद करने की दिशा में नहीं है।

तीसरी बात यह है कि 2002-03 में जहां डिमांड के ऊपर पूरे देश में 21.38 मिलियन टन 2006-07 में टेंथ फाइव इयर प्लान में किया गया है और इसकी डिमांड तीन मिलियन टन बढ़ गयी है और मिनिस्ट्री ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी जिसके चेयरमैन खुद उर्वरक मंत्री हैं उन्होंने यह डिसिजन लिया था कि सिंदरी खाद कारखाने को ही हमलोग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करें।

यह डिसिजन था आपका जुलाई महीने का और 5 सितंबर को सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह कहती है कि हमलोग बंद कर देंगे और दो महीना में यह डिसिजन, पहले बोलती है कि इसको बढ़ायेंगे, फिर बोलती है बंद कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि पूरा सदन, हमलोग की यह भावना है, पूरा सदन इसको, जैसे एचइसी में हमलोग पारित किये , इस कारखाना के मुद्दे पर भी पूरे सदन से सर्वसम्मति से पारित करें एवं मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री खुद इसको देंखे ताकि यह फिर से दुबारा चालू किया जाय।

फुरकान अंसारी : महोदय....

पशुपतिनाथ सिंह (मंत्री): महोदय, गैर-सरकारी संकल्प पर यहां परिचर्चा होगी ? इसके लिए दूसरी तरह से आप इसको परिचर्चा के लिए लायें लेकिन यह न नियमानुकूल हो रहा है और न परम्परा के अनुकूल हो रहा है कि गैर-सरकारी संकल्प पर जिनका गैर- सरकारी है, वह प्रश्न उठायेंगे सरकार के उत्तर से वह संतुष्ट हुए, नहीं संतुष्ट हुए , तो फिर वोटिंग के लिए आयेंगे लेकिन इस तरह से परिचर्चा, जैसा माननीय महेन्द्र सिंह जी ने सवाल को उठाया सिन्दरी को बचाने की दिशा में उसका हमने जवाब दिया। फिर, वह दूसरा गैर- सरकारी संकल्प उसी विषय पर, और फिर उरके बाद परिचर्चा हो रही है तो यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है।

अरूप चटर्जी: महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है। गैर-सरकारी संकल्प सदन में लाए गए, यह बात सच है लेकिन...

समरेश सिंह: विषय ठीक है, विधान सभा सिंदरी को बंद करने के पक्ष में है? यह विषय आया है तो सरकार शत- प्रतिशत सिंदरी को पुनर्जीवित करना चाहती है और यह प्रमान्ति करने के लिए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। यह हमारा विचर है।

फुरकान अंसारी: महोदय, पिछले दिनों की भी आप याद रखें। उपाध्यक्ष महोदय सर्वसम्मति से हमलोग विधानसभा में यहां पारित किए थे कि धनबाद को जोन बनाया जाए। एक फैसला हुआ। दूसरा यह हुआ कि हटिया को बंद नहीं होने दिया जाए। तीसरा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए कि सिंदरी किसी भी कीमत पर बंद नहीं हो। इसमें इस बार यह निर्णय लिया जाए, हमारे दल की यह राय है और मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से यह राय बने।

महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव लिया धनबाद को जोन बनाने के लिए।

लेकिन उसके बाद भी वहां चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी की सरकार दिल्ली में है इसलिए सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए। यहां भाषण देने, जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। आपको केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। हमलोग यहां सर्वसम्मति से निर्णय लेने के तैयार हैं।

पशुपति नाथ सिंह(मंत्री): महोदय 02.11.02 को बीआईएफआर ने इसको बाईडिंग अप करने का निर्णय लिया। अब बीआईएफआर ने निर्णय लिया तो यहां पर रिभाईभल पैकेज केन्द्र सरकार को देना था। उनका रिभाईभल पैकेज साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का है। यह थोड़े दिनों के लिए चल सकेगा।

यह केन्द्र सरकार को बीआईएफआर को देना है लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार भूमिका नहीं निभा सकती है तो मैं कहना चाहता हूं कि यहीं पर एचईसी राज्य सरकार से सहयोग मांग रही है और राज्य सरकार अपने औद्योगिक नीति के तहत उसको सहयोग दे रही है। इसी तरह से सिंदरी प्रबंधन को राज्य सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखना चाहिए ताकि उस पर विचार कर राज्य सरकार उसको सहयोग करे लेकिन यह बात नहीं हो रही है।

फुरकान अंसारी: आप उनको सलाह दीजिए।

पशुपति नाथ सिंह (मंत्री): सलाह दिए लेकिन वह सलाह मानने के लिए तैयारी नहीं हैं। इसी बात को मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, इसी बात को फर्टिलाइजर मिनिस्टर को लिखा ।प्रधानमंत्री से डेलीगेशन मिलकर इस बात का आग्रह किया कि सिंदरी को बचाना चाहिए लेकिन सिंदरी का जो निर्णय है उसको पैकेज देना है। आज के परिवेश में रिभाईभिलिटी है कि नहीं, कि कोयला आधारित फर्टिलाइजर कंपनी चल सकती है। अगर नहीं आग्रह करते, सरकार की नीयत में खोट रहती तो प्रधानमंत्री जी से शिष्टमंडल नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में।

फुरकान अंसारी: अगर आप खुलवा देते हैं तो आपका जय जयकार होगा।

पशुपति नाथ सिंह (मंत्री): कौन नहीं चाहता है जय जयकार हो । लेकिन इतने दिनों से जो स्थिति चौपट हो गयी है उसके अनुसार ऐसा हुआ है। अब केन्द्र सरकार निर्णय लेगी।

महेन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक बात कहूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी ने जो बातें कही है कि सरकार इसको बचाना चाहती है। मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली गए ।

अरूप चटर्जी तो तर्क दे रहे हैं कि किसी तकनीकी समिति ने इसके पुनर्जीवन की आशा व्यक्त की है। तीसरी बात , मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में खाद की जरूरत बढ़ेगी। आस पास के इलाकों में खाद के कारखाने नहीं हैं यानी भौतिक परिस्थितियां भी हैं और सरकार भी चाहती है। अगर यह संकल्प पारित हो जाय तो सरकार के उस इरादे को और मजबूती मिलेगी। इसलिए हमें लगता है कि उद्योग मंत्री जी को इस प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए।

पशुपति नाथ सिंह (मंत्री): वह राज्य सरकार दे रही है। सिर्फ पॉलिटिकल माईलेज लेने के लिए इन प्रश्नों को उठाए जा रहे हैं। इस राज्य के मुखिया ने प्रधानमंत्री जी से जाकर आग्रह किया, उनको पत्र लिखा तो इसके बाद भी क्या कोई चीज बची ? मेकन के बारे में मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार को लिखा, एचईसी के बारे में प्रस्ताव पास किए , सरकार की ओर से पत्र लिखा गया । यह कार्रवाई हुई है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

समरेश सिंह (मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एचइसी के बारे में मेकन के बारे में जब विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सकती है सिंदरी के बारे में प्रस्ताव पास करने में क्या दिक्कत है?

व्यवधान

गिरिनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर भारत सरकार के पास भेज दीजिए न।

उपाध्यक्ष: अगर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाए तो क्या आपति है उद्योग मंत्री जी ?

पशुपति नाथ सिंह(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने तो कर दिया है। इसमें सर्वसम्मति है क्या दिक्कत है।

उपाध्यक्ष: ठीक है, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया।

पशुपतिनाथ सिंह(मंत्री):उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार न पहले एक प्रस्ताव भेज दिया है।

आखिर स्पीकर क्यों भड़के

झारखंड की गोमिया और सिल्ली उप चुनाव में सत्तापक्ष की हार से भाजपा में तूफान मचा हुआ है। भाजपा और आजसू नेता एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। गोमिया में तीसरे स्थान पर पार्टी प्रत्याशी के खिसकने से वरीय नेता परेशान हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने इशारों-इशारों में पार्टी के राज्य नेतृत्व पर तल्ख टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सार्वजनिक रूप ने कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके विधानसभा अध्यक्ष की नयी टिप्पणी की पार्टी के अंदर खूब चर्चा हो रही है। उरांव ने सधे शब्दों में अपने मन की पीड़ा साझा की है और सीधा व सपाट सुझाव भी दिया है। वे चाहते हैं कि पार्टी की रणनीतिक चूक की समीक्षा हो। इसके लिए उन्होंने आपसी तकरार और द्वेष का त्याग करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर अपनी बात कह चुके उरांव की सलाह पर ढेर सारी टिप्पणियां भी आई हैं, जिनमें उनकी बात का समर्थन किया गया है।

स्पीकर का इशारा मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी रघुवर को केवल अमित शाह की वजह से आसानी से मिल गयी।

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि राजनीति, श्रेष्ठ राजनीति तभी है जब हम आपसी तकरार, द्वेष को त्याग कर यह समीक्षा करें कि आखिर चूक कहां हो गई। जनता हमसे प्रतिनिधि के रूप में क्या-क्या अपेक्षा रखती है? अंत में हार स्वीकार कर आगे की रणनीति भी इसी आधार पर बनाई जानी चाहिए। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है जिसकी पूछ एवं प्रशंसा सब जगह होती है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई चीज कड़ी मेहनत और संघर्ष के पश्चात मिलती है तो आप उसके प्रति ईमानदार भी रहते हैं क्योंकि आप उस चीज की अहमियत समझते हैं। उनका इशारा मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी रघुवर को केवल अमित शाह की वज़ह से आसानी से मिल गयी। भाजपा में इस बात को लेकर भी बातें उठ रही है कि गोमिया में प्रत्याशी तय करने से लेकर नामांकन पत्र भरने और चुनाव अभियान में वरीय नेताओं की अनदेखी हुई। सलाह-मशविरा की बात तो दूर, उन्हें पूछा तक नहीं गया। ऐसे में इन नेताओं ने खुद को सीमित रखा।

इन सब के बीच दल के भीतर पैदा हुई सुगबुगाहट के अलावा भाजपा के समक्ष आजसू को साथ बनाए रखना भी एक चुनौती है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो के तेवर तल्ख हैं।

भाजपा सांसद और कई नेताओं के भीतरघात के बाद वो भाजपा के साथ अपनी पार्टी का तालमेल तोड़ सकते हैं।

बहरहाल इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से सत्ताधारी खेमें में खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ गोमिया में पार्टी की हार हुई है दूसरी तरफ हार के बाद सहयोगी दल आजसू ने भी हार का ठीकरा बीजेपी के ऊपर ही फोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मिली इस हार से राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा न हो इसके लिए उनमें जोश भरने की जरुरत है

लेकिन इस मौके पर पार्टी के बड़े नेताओं के बोल कुछ और ही हैं। ऐसे बयानों से पार्टी के भीतर भ्रम तो बनेगा ही इसके साथ ही विपक्ष को भी सत्ताधारी दल पर जोरदार हमला करने की मौका मिलेगा। हालांकि, पार्टी के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो दिनेश उरांव की बात से पूरी तरह इत्तिफाक रखता है और विधानसभा अध्यक्ष की बात को सही ठहराता है। पार्टी के अंदर और वर्तमान सरकार को दिनेश उरांव द्वारा की गयी सार्वजानिक टिप्पणियां असहज करती रही हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज़ होकर कुछ माह पूर्व उन्होंने सुरक्षाकर्मी और गाड़ियां वापस कर दी थी। वे विधानसभा अध्यक्ष को मिले सरकारी बंगले का भी उपयोग नहीं करते। कई मसलों पर उनकी बेबाक राय इसकी वजह है। जनवरी माह में उन्हें स्पीकर पद से हटाने की चर्चा भी जोरों से चली थी।

लेकिन बाद में हाईकमान ने वक्त की नजाकत को देखते हुए स्थिति को संभाल लिया था। बता दें कि बजट सत्र के दौरान झारखण्ड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन उस वक्त राज्य को शर्मसार होना पड़ा जब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्ष के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। हुआ यूं कि विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव नेता, प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन सहित अन्य झामुमो सदस्यों को सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करने को कह रहे थे ताकि जरूरी संशोधन और विधेयकों को सदन पटल पर रखा जा सके और उस पर सुचारू रूप से बहस हो सके। लेकिन झामुमो नेता हेमंत सोरेन सरकार के स्थानीय नीति का विरोध कर रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी सीट से उठे और स्थानीय नीति पर सरकार का पक्ष रखने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही स्थानीय नीति घोषित की गई। झामुमो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनको झंडा ढोने का बहाना नहीं मिल रहा इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। और स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की जुबान फिसल गई और उन्होंने विपक्ष को अपशब्द (गाली) दे दी। इतना सुनते ही झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन की मर्यादा तक भूल गए हैं और खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

झामुमो नेता हेमंत सोरेन सरकार के स्थानीय नीति का विरोध कर रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी सीट से उठे और स्थानीय नीति पर सरकार का पक्ष रखने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही स्थानीय नीति घोषित की गई। झामुमो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनको झंडा ढोने का बहाना नहीं मिल रहा इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं।

@Rajneeti_Guru | @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

जिस प्रकार सूबे की सियासत से कई बड़े नेताओं को किनारा किया जा रहा है और बड़े फैसलों पर कुछ ही लोग मिलकर अपनी राय रख रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर असंतोष बढता जा रहा है।

इसके बाद झामुमो ने सदन से वॉक आउट किया और विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हिदायत दी थी जिसको लेकर दोनों को बीच नोंकझोंक भी हुई थी इसके बाद ये खबरें आने लगी कि विधानसभा अध्यक्ष रघुवर दास के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सकते हैं जिससे मुख्यमंत्री को उनके द्वारा की गई गलती का अहसास हो।

इस बीच राजनीतिक हलकों में ये बातें खूब चर्चा में आयीं कि झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मामले में स्पीकर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर दिनेश उरांव सख्त कदम उठा सकते हैं। हालांकि इसके बाद सूबे के कई बड़े नेताओं और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दखल के बाद मामले को सुलझा लेने की बात सामने आयी लेकिन इस बीच सुनवाई के दौरान कई दफा उनकी तल्ख टिप्पणियों ने सरकार को असहज किया है। अब उपचुनाव के परिणाम को लेकर उनकी ताजा टिप्पणी से भी विवाद गहरा सकता है।

इधर, सूबे की सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सरकार काम कर रही है उससे राज्य का एक बड़ा वर्ग नाराज चल रहा है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भूमि संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरा है और आदिवासी मूलवासी छवि बनी है उससे भाजपा के कई विधायक अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देने में असहज महसूस करे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कहीं न कहीं सरकार के काम काज से बहुत खुश नहीं हैं।

सरकारी अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी वे कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर जिस प्रकार सरकार ने पूर्व मुख्यसचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय और एडीजी अनुराग गुप्ता जैसे आरोपी अधिकारियों का बचाव किया और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया उसके ऊपर भी विधानसभा अध्यक्ष काफी नाराज थे और इस मामले के बाद सरकार की जो छवि जनता के बीच बनी उस पर उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था।

जानकारों की मानें तो विधानसभा अध्यक्ष बहुत जल्द कोई बयान नहीं दिया करते लेकिन उपचुनाव में मिली हार के बाद जो उन्होंने कहा है उससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वे पार्टी और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार की कार्यशैली अगर नहीं सुधरी तो आगे मुश्किलें बढ. सकती हैं। राज्य की राजनीति की समझ रखने वाले जानकारों की मानें तो इसके पीछे भी कई अलग-अलग संदर्भ हैं जिसे एक साथ जोड़ने की जरुरत है।

बताया जाता है कि जिस प्रकार सूबे की सियासत से कई बड़े नेताओं को किनारा किया जा रहा है और बड़े फैसलों पर कुछ ही लोग मिलकर अपनी राय रख रहे हैं उससे पार्टी के अंदर असंतोष बढता जा रहा है। पार्टी के दो कद्दावर नेता सरयू राय और अर्जुन मुंडा अलग-थलग पड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का मिशन 14 और विधानसभा का मिशन 60 प्लस दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है। कहीं न कहीं दिनेश उरांव को ये बातें अखरने लगी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सबको साथ लेकर चलने की अपनी कवायद से दूर होता जा रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले चुनावों में स्थिति बदल सकती है जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए समय पर अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो स्थिति पलट सकती है।

झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मामले में स्पीकर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर दिनेश उरांव सख्त कदम उठा सकते हैं। हालांकि इसके बाद सूबे के कई बड़े नेताओं और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दखल के बाद मामले को सुलझा लिया गया।

कॉरपोरेट और दलालों की भाषा बोल रही सरकार?

झारखण्ड में लगातार जन संघर्ष कर असली मुद्दों को लोगों के बीच ले जानेवाले झाविमो के अध्यक्ष और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से राजनीतिगुरु ने लम्बी बात की पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश...

सीएनटी- एसपीटी पर विपक्षी पार्टियों के विरोध और व्यापक जनाक्रोश के कारण सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इसे आप कैसे देखते हैं।

पहली बात तो यह कि सरकार का सीएनटी- एसपीटी के लेकर लाया गया संशोधन ही बिलकुल आधारहीन और गलत था। सरकार संशोधन के जरिये जो भी बचा हुआ जमीन था उसे लेने की साजिश कर रही है। इसलिए इस तरह का विरोध होना लाजिमी था। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनमें भी कुछ लोग जिन्होंने काफी दिनों तक अपनी जुबान बंद रखी थी वो भी खुल कर इसके विरोध में सामने आ गए। कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो ने भी इस मुद्दे पर सरकार के निर्णय का विरोध किया। आम जनता के व्यापक विरोध के कारण सरकार को अंततः विधेयक वापस लेना पड़ा। इस फैसले के खिलाफ 194 संगठनों ने राज्यपाल और केंद्र को ज्ञापन सौंपा था। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।

> **कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो ने भी इस मुद्दे पर सरकार के निर्णय का विरोध किया। आम जनता के व्यापक विरोध के कारण सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा।**

सीएनटी- एसपीटी को विकास की राह में बाधक बताया जा रहा है। देखा जाय तो सरकार आज जमीन दलालों और कारपोरेट घरानों के चंगुल में है।

आज की तारीख में भी सरकार के पास काफी जमीन है। सरकार ने खनन, कल- कारखाने लगाने के लिए 15 लाख हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। जो लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वे इस एक्ट को विकास में बाधक बताते हैं।

वहीं आज की तारीख में भी सरकार के पास काफी जमीन है। सरकार ने खनन, कल- कारखाने लगाने के लिए 15 लाख हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। जो लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वे इस एक्ट को विकास में बाधक बताते हैं। एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण का पूर्व से ही प्रावधान है। तो फिर इस नए संसोधन की जरूरत ही क्या है। सरकार को चाहिए कि वो एक आयोग बनाए जहां रैयतों, किसानों की बात सुनी जाए। फिर जो सुझाव आयेंगे उस पर विचार करे। सरकार कारपोरेट के लिए नहीं बनी है। जब रेंट या लीज पर अधिकतर कार्य किए जा रहे हैं तो फिर रैयतों, किसानों को बेदखल क्यों किया जा रहा है।

झारखंड राज्य के गठन को आज 17 साल हो गए, राज्यवासियों की कई आकांक्षाएं थी, पर इतने वर्षों बाद झारखंड को आप कहां खड़ा पाते हैं।

जब भी हम झारखंड या किसी भी अन्य राज्य की बात करते हैं तो हमें बाकी राज्यों की परिस्थितियों को भी देखना होगा। सभी राज्यों के संसाधन अलग- अलग हैं इसलिए परिस्थितियां भी भिन्न हैं। इसलिए विकास का मॉडल एक जैसा नहीं हो सकता। राज्य की भौगोलिक स्थिति से लेकर अन्य कई चीजें हैं जो उसके आर्थिक विकास का मानक बनती हैं। कहीं उद्योग तो कहीं टूरिज्म की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सभी के विकास का मॉडल एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे अगर दिल्ली की बात की जाय तो वहां ट्रेडिंग की काफी संभावनाएं हैं इसलिए वह इस क्षेत्र में तेजी से विकास भी कर रहा है। वहीं गोवा और केरल जैसे राज्य भी हैं जो टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वहां उस प्रकार की संभावनाएं हैं।

इसलिए हर राज्य के विकास के पैमाने अलग- अलग हैं। झारखंड के संदर्भ में रोड मैप बनाने की जरूरत है। राज्य को बनाने में आजादी के बाद से ही काफी लंबा संघर्ष किया गया है। झारखंड बनने के बाद लोगों को लगा कि अब इस क्षेत्र में ढेर सारे कल -कारखाने लगेंगे।

नया प्रदेश बनेगा तो तेजी से विकास होगा। नया राज्य तो बना लेकिन दुर्भाग्य से आज भी समस्याएं वही हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि आज स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। लोगों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आज भी सरकार उसी रास्ते पर है। आज भी वही बुनियादी समस्याएं हैं जो राज्य बनने के पहले थीं। राज्य आज भी वहीं खड़ा है। इसलिए झारखंड में विकास का मॉडल क्या होगा इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पर यह अफसोस की बात है कि सत्ता में बैठे लोग इस पर विचार के लिए तैयार नहीं हैं। वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कल- कारखाने, डैम, खदान के नाम पर रैयतों से सरकार जबर्दस्ती जमीन लेने पर उतारू है।

नया राज्य तो बना लेकिन दुर्भाग्य से आज भी समस्याएं वही हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि आज स्थिति और भी ज्यादा भयावह है।

एक ओर सरकार हर दिन अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं दूसरी ओर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। सरकार ने जमीन लेने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं।

राज्य वहीं है, जहां पहले था, अगर राज्य बनने के तुरंत बाद इसको ध्यान में रखकर रोड मैप तैयार किया जाता तो आज स्थिति कुछ अलग होती। जहां तक राज्य के गठन के पहले की बात है तो उस समय भी कल-कारखाने और डैम बने और उस समय भी काफी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ था। लेकिन उस समय राज्य की जनसंख्या कम थी। अब यह जनसंख्या सवा तीन करोड़ हो गई है।

आने वाले समय में रहने के लिए भी जमीन नहीं रह जाएगा। आज स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब है। अभी देख लीजिए हरमू बाई-पास में रहने वाले लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया है। ऐसे ही गांवों से लोगों को उजाड़ा जाएगा तो आगे उनके जीविकोपार्जन की भी समस्या पैदा हो जाएगी। उनके पास कमाई का कोई और साधन भी नहीं बचेगा।

वे कहां जाएंगे। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को सोचना होगा, उन्हें इसके लिए रोड मैप तैयार करना होगा।

जेवीएम अगले चुनाव में किन सवालों को लेकर जनता के बीच जायेगा

देखिए, विस्थापन, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे हमेशा चुनाव के केंद्र में रहे हैं। चाहे वह एचइसी का मुद्दा हो, मैथन डैम हो या फिर तेनुघाट से विस्थापन का मुद्दा हो। हमारा प्रयास है कि इन जन मुद्दों को गांव- गांव में ले जाकर लोगों को अपने हक से अवगत कराया जाय।

इस चुनाव में भी हम इन्हीं समस्याओं के साथ जनता के बीच जायेंगे। लोगों को जागरूक करना होगा कि किस प्रकार उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत बेदखल किया जा रहा है। सरकार के रवैये से उन्हें अवगत कराया जाएगा। बड़कागांव से लेकर दुमका और खूंटी तक जन संघर्ष को बंदूक की बदौलत किस प्रकार कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता प्रदीप यादव को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। पूरे प्रदेश में अलग-अलग जारी प्रतिरोध को मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनायेंगे क्योंकि इन सभी मुद्दों का समाधान तो राजनीतिक तौर पर ही होगा, इसलिए यह जरूरी है कि हम इसे ही केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दा बनाएं ।

पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने की बात करने वाली पार्टी पर आज भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लग रहे हैं । आप क्या कहेंगे। देखिए ,आज झारखंड में सबसे खराब नेतृत्व है। कहीं भी देख लीजिए चारो ओर अव्यवस्था का माहौल है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। मैट्रिक और इंटर में 60 फीसदी बच्चे फेल हो रहे हैं। बड़ी- बड़ी बात करते हैं कि राज्य में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ रही हैं एमसीआई ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। सदर अस्पताल को चलाने के लिए कई बार टेंडर निकाला गया और इसको बनाने से लेकर मरम्मती में करोड़ों की लूट की गई। सरकार आज तक एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं कर पायी है। वहीं पतरातू थर्मल की जमीन एनटीपीसी को कौड़ी के भाव में दे दी गई। अडाणी को जमीन देने के लिए ऊर्जा नीति 2012 को ही बदल दिया गया। ये सारे मुद्दे चुनाव में भी रहेंगे। झारखंड से खनिजों का दोहन हो रहा है। राज्य को रेगिस्तान बनाया जा रहा है। जबकि खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से भी किया जा सकता है। खादानों को खनन के बाद जस का तस छोड़ दिया जा रहा है। आज तक एक एक-ड़ जमीन भी समतल नहीं किया गया है। पर ये सब अब चलने नहीं दिया जाएगा। लोगों को इस षडयंत्र के खिलाफ जागरुक किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि ये बातें लोगों की जुबान पर आये। इसके लिए हम गांव-गांव जाकर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे।

> सरकार के पास ने तो सोच है और न ही कोई विजन। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

ऐसा अक्सर देखा गया है कि जेवीएम सत्ता में नहीं आये इसके लिए बीजेपी नेता आपके बीजेपी में आने की बात करते रहते हैं। क्या यह चुनाव जेवीएम विपक्षी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। काठ की हांडी बार- बार नहीं चढ़ाई जाती, चुनाव के पहले और बाद में बीजेपी के नेताओं ने किस प्रकार लोकतंत्र का मजाक बनाया और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ये सबकुछ जनता देख रही है। इसलिए इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। जहां तक गठबंधन की बात है तो इसकी कोशिश करेंगे। जनहित के लिए विपक्ष के महागठबंधन की अगर गुंजाइश होती है तो जरूर करेंगे। लेकिन ये बातें समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। राजनीति में समझौते की गुंजाइश हमेशा रहती है। चुनाव के समय देखा जाएगा कि किस पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। जेवीएम के एमएलए को तोड़ा गया, इस मुद्दे पर पार्टी लगातार आवाज उठा रही है।

विधानसभा अध्यक्ष से भी मामले के जल्द से जल्द निपटारे की मांग की जा रही है। पर जिस प्रकार सुनवाई में देरी हो रही है इस पर आप क्या कहेंगे।

मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक मर्यादाएं तोड़ दी हैं। वह बेईमानी पर उतर आया है।

संविधान की 10 वीं अनुसूची में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों की सदस्यता रद हो सकती है। पूरी दुनिया ने देखा है कि ये सभी जेवीएम के चुनाव चिन्ह पर लड़े। पर बीजेपी ने इन्हें पद और पैसे का लालच देकर पार्टी में लाया कुछ लोगों को मंत्री बनाया वहीं कुछ को पैसे भी दिए गए। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझ कर लटका रहे हैं। अगर कानून सम्मत है तो तुरंत फैसला दें। इनका असली चेहरा जनता समझ रही है। जेवीएम भी चुनाव में इन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएगा।

महागठबंधन भाजपा के लिए खतरे की घंटी

निशिकांत से गोड्डा छीनने की तैयारी

रंजीत, देवघर

झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल झामुमो, झाविमो एवं वाम मोर्चा ने भी कांग्रेस की रणनीति में हमसफर बनने की हामी भरी है। इसकी झलक राज्यसभा चुनाव में दिख चुकी है और सिल्ली, गोमिया उपचुनाव में भी इसका असर दिखा। अब बारी गोड्डा लोकसभा सीट की है।

कर्नाटक में भाजपा की सरकार गिराने और कांग्रेस- जेडीएस सरकार बनाने के बाद जाहिर है विपक्ष एकजुट है, उत्साहित है। इसकी झलक शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखी। मिशन 2019 का बिगुल विपक्ष ने फूंक दिया गया है। इसके साथ ही महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी काम शुरू हो गया है। देखा जाय तो कमोबेश सभी विपक्षी दलों के नेता इस मुहिम के लिए हामी भी भर चुके हैं।

देश के हर क्षेत्र में कमजोर हो चुकी कांग्रेस अपनी हार का दर्द एवं सत्ता से बाहर होने की बेचैनी में विपक्षी दलों से मिलकर महागठबंधन को धारदार बनाने की कवायद कर रही है। इसके माध्यम से भाजपा को कड़ी टक्कर देना चाहती है। झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल झामुमो, झाविमो एवं वाम मोर्चा ने भी कांग्रेस की रणनीति में हमसफर बनने की हामी भरी है। इसकी झलक राज्यसभा चुनाव में दिख चुकी है और सिल्ली, गोमिया उपचुनाव में भी इसका असर दिखा।

इधर, संथाल परगना के तीनों सीटों पर महागठबंधन की नजर है और गोड्डा लोकसभा सीट को हर हाल में जीतना है। वैसे अभी भी दुमका सीट पर झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं राजमहल सीट पर विजय हांसदा का कब्जा है जिसे बचाए रखने की भी चुनौती है। बता दें कि राजमहल सीट पहले भी वर्तमान सांसद विजय हांसदा के पिता थॉमस हांसदा के कब्जे में रहा है, इस सीट पर आदिवासी और मुस्लिम मतदाता हमेशा कांग्रेस के पक्ष में वोट करते रहे हैं। दुमका सीट दिशोम गुरु व झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की परंपरागत सीट रही है। इसलिए गोड्डा सीट पर भी कब्जा जमाने की कोशिश के तहत इस बार किसी नए दमदार व स्वच्छ छवि के हिन्दू उम्मीदवार की तलाश की जा रही है, जो महागठबंधन को जीत दिला सके। पूर्व में कांग्रेस ने 2009 एवं 2014 के चुनाव में पार्टी के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी को उम्मीदवार बनाया था लेकिन उन्हें दोनों ही मर्तबा हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे 2004 के चुनाव में फुरकान अंसारी जीत दर्ज चुके हैं।

विपक्षी नेताओं की राय है कि गोड्डा सीट पर किसी दमदार स्वच्छ छवि के हिन्दू उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि हिन्दू वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा के वोटरों को अपने खेमे में लाया जा सके

लेकिन इधर उनकी लगातार दो बार हार के कारणों में मुख्य कारण हिन्दू वोटों का गोलबंद होना बताया जाता है। हिन्दू मतदाताओं की नजर में फुरकान अंसारी जब सांसद थे उस दौरान वे अधिकतर मुस्लिम क्षेत्रों में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, जिससे हिन्दू मतदाताओं में उनकी पकड़ ढीली हो गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में सांसद निशिकांत दूबे ने फुरकान अंसारी को 6407 साधारण मतों के अंतर से हराया था जबकि 2014 में निशिकांत दूबे ने फुरकान अंसारी को 60 हजार 682 मतों के बड़े अंतर से हराया है।

तीसरे नंबर पर रहे झाविमो के प्रदीप यादव को कुल 1 लाख 93 हजार 506 मत प्राप्त हुए थे, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस से दामोदर सिंह मेलर एवं बसपा के मनराज ने भी क्रमश 28 हजार 246 एवं 20 हजार 871 मत प्राप्त किए थे। ऐसी स्थिति में विपक्ष की गोलबंदी व एकजुट होने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि विपक्षी दलों का महागठबंधन अगर कामयाब हो गया तो निशिकांत के लिए सीट बचाना मुश्किल हो सकता है।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल झामुमो, झाविमो एवं वाम दलों के नेताओं की राय है कि गोड्डा सीट पर किसी दमदार स्वच्छ छवि के हिन्दू उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि हिन्दू वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा के वोटरों को अपने खेमे में लाया जा सके। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एवं झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी इसके पक्ष में दिख रहे हैं।

गोड्डा लोकसभा सीट को जीतने के लिए वोटों के

विपक्ष की गोलबंदी व एकजुट होने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि विपक्षी दलों का महागठबंधन अगर कामयाब हो गया तो निशिकांत के लिए सीट बचाना मुश्किल हो सकता है।

समीकरण पर गौर करें तो महागठबंघन में झामुमो का वोट बैंक आदिवासी मतदाता, कांग्रेस व झामुमो का मुस्लिम तथा झाविमो का यादव मतदाताओं के साथ हिन्दू में दलित व पिछड़े वर्ग में पकड़ बनाई जाए तो महागठबंधन सीट निकाल सकता है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 34 हजार है जबकि मुस्लिम साढ़े तीन लाख तथा यादव मतदाताओं की संख्या लगभग ढाई लाख है।

संथाल परगना क्षेत्र में झामुमो का आदिवासी व संथाल के अधिकांश वोटों पर आज भी पकड़ काफी मजबूत है, जो दिशोम गुरू के इशारे पर ही अपना रुख तय करते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मुहिम में शंका सिर्फ झाविमो महासचिव प्रदीप यादव से ही है, जिन्हें अबतक के राजनीतिक इतिहास में संथाल परगना के सबसे अधिक महत्वाकांक्षी नेताओं में से जाना जाता है। कहा जाता है कि उनकी ही जिद एवं दबंगई के कारण झाविमो के अधिकांश दमदार नेता पार्टी छोड़ कर बाबूलाल से बिछड़ गए।

इस अलगाव से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं उन नेताओं को खासा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदीप यादव ने 2000 में गोड्डा सीट पर भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी, उसके बाद 2009 व 2014 में भी झाविमो से चुनाव लड़े पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

प्रदीप यादव गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं के शीर्ष नेता रहे हैं और इस कारण यह सीट जीतने के लिए यादवों का वोट पाना महागठबंधन के लिए जरूरी है। क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता किसी भी हाल में भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं।

प्रदेश के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी एवं पूर्व विधानसभाध्यक्ष व पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम मुस्लिम वोट को महागठबंधन के पक्ष में करने में सक्षम हैं लेकिन टिकट कटने का दर्द लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी कितना अहम रोल महागठबंधन के पक्ष में निभा पाऐंगे, वह समय ही बता पाएगा। संभवत उन्हें टिकट से वंचित करने की भरपाई अन्य तरीके से करना पड़ सकता है। यह सब निर्भर करता है विपक्षी दलों के नेताओं की सर्वसम्मती पर।

दूसरी ओर, भाजपा सांसद निशिकांत दूबे 2009 एवं 2014 में लगातार दो बार दमदार जीत दर्ज कर चुके हैं और उनका उत्साह भी चरम पर है। सांसद निशिकांत की जीत के दावे में दम भी है, कारण है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अलावा संथाल परगना के विकास में अब तक किए गए प्रयासों पर गौर करें तो शायद अबतक के सांसदों के कार्यों पर निशिकांत दूबे भारी पड़ते दिख रहे हैं।

बहुर्चिचत देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण, एम्स की स्थापना, गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के अलावा कई छोटी-बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा श्रेय निशिकांत दूबे को ही है,। 2004 में कथित बाहरी के रूप भाजपा का टिकट लेकर आए निशिकांत ने अपने ही पार्टी में कई झंझावातों से गुजरते हुए जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंचे। उसके बाद 2014 में अपने दमदार छवि एवं कार्यों के बल पर जीत दर्ज की है। आज निशिकांत भाजपा के कई स्थानीय नेताओं की किरकिरी बने हुए हैं।

निश्चित ही क्षेत्र में उनके प्रयासों से राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर संथाल परगना के कई पर्यटन स्थलों को लाया जा सका, मसलन बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, मलूटी।

इन पर्यटन स्थलों के विकास में निशिकांत ने अहम्‍ भूमिका अदा की है। शहरी मतदाताओं में निशिकांत दूबे की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। वैसे गोड्डा लोकसभा सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है, यहां से 1996,1998, 1999, 2000, 2009 एवं 2014 में भाजपा उम्मीदवार विजयी रहे हैं।

इस क्षेत्र की राजनीति को नजदीक से समझने-बूझने वाले जानकारों की मानें तो विपक्षी दलों की ओर से उम्मीदवार के चयन में नए चेहरे की तलाश में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें जरमुंडी के कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख के नाम की भी चर्चा है, जिनकी स्वच्छ, सादगी, और युवा नेता की छवि हिन्दू वोटरों में सेंध लगा सकती है। कहा जा रहा है कि निशिकांत दूबे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, और सीट निकाल सकते हैं। जानकारों की मानें तो इस सीट पर कोई ओबीसी उम्मीदवार भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। सियासी गणित को देखते हुए इस क्षेत्र में एक उभरता हुआ चेहरा बजरंगी प्रसाद यादव का भी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्री यादव ने गोड्डा क्षेत्र में काफी काम किया है। वे साफ छवि के नेता तो हैं ही इसके साथ ही उनकी जमीनी पकड़ भी है। समाज के पिछड़े तबकों की लड़ाई वे लगातार लड़ते आए हैं। उनके जूझारू तेवर को देखते हुए कांग्रेस के अंदर खाने इस बात की जोरशोर से चर्चा हो रही है कि उन्हें इस सीट पर खड़ा किया जा सकता है। इस लोकसभा सीट पर पिछड़ों की आबादी हार-जीत का फैसला करती है इस लिहाज से बजरंगी प्रसाद यादव अगर महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। गोड्डा सीट पर कामयाबी मिल सकती है।

गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अलावा संथाल परगना के विकास में अब तक किए गए प्रयासों पर गौर करें तो शायद अबतक के सांसदों के कार्यों पर निशिकांत दूबे भारी पड़ते दिख रहे हैं।

हालांकि निशिकांत दूबे ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार क्षेत्र में काम किया है और अपनी जमीन पकड़ बनाई है उससे महागठबंधन को एक ठोस रणनीति के तहत काम करना होगा। साथ ही वैसे उम्मीदवार को उतारना होगा जो निशिकांत के मुकाबले में किसी प्रकार से कम नहीं हो।

पिछले दिनों साहेबगंज में पिछड़ों की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें आरक्षण के सवाल पर आर-पार की लड़ाई का संकल्प लिया गया। ऐसी लड़ाई प्रदेश के हर हिस्से में शुरू हो चुकी है।

आरक्षण के सवाल पर धधक रहा झारखंड

सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव करके झारखंड के 11 जिलों में उसी प्रकार की स्थानीय नीति को लागू किया जो शेष झारखंड के लिए पहले से लागू था लेकिन 14 प्रतिशत आरक्षण और जिला रोस्टर 0 से 9 प्रतिशत आरक्षण का मामला अब तेजी से गर्माने लगा है।

झारखंड में ओबीसी आरक्षण का मामला अब धीरे-धीरे हो गर्माने लगा है बता दें कि मंडल कमीशन के अनुरूप झारखंड में ओबीसी के लिए राज्य स्तर पर केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है राजनीति गुरु पत्रिका ने अपने पहले अंक में पिछड़ों के हक और हकमारी की आवाज को उठाया था उसके बाद सरकार के भीतर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति की विसंगतियों पर चर्चा होने लगी। विगत विधानसभा सत्र के दौरान जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर 14 सत्ताधारी एवं विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाया कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आरक्षण रोस्टर के हिसाब से यदि नहीं निकाला जाता है, तो हम लोग बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे इस दबाव के बाद सरकार को झुकना पड़ा और प्रारंभिक परीक्षा की लिस्ट दोबारा निकालना पड़ा। ओबीसी विधायकों के बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने आनन-फानन में स्थानीय एवं नियोजन नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अमर बाउरी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया राजनीतिक गुरु द्वारा उठाए गए विसंगतियों का असर सरकार के भीतर और सरकार के बाहर साफ-साफ दिखने लगा। सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव करके झारखंड के 11 जिलों में उसी प्रकार की स्थानीय नीति को लागू किया जो शेष झारखंड के लिए पहले से लागू था लेकिन 14% आरक्षण और जिला रोस्टर 0 से 9% आरक्षण का मामला धीरे-धीरे गर्माने लगा है। झारखंड के पांचों प्रमंडल में पिछड़ा वर्ग संघर्ष के बैनर तले आरक्षण की मांग उठने लगी है सबसे पहले इसकी शुरुआत संथाल परगना प्रमंडलीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा बासुकीनाथ एवं गोड्डा में बैठक कर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत पूर्व मंत्री लालचंद महतो की अध्यक्षता में शुरू की गई थी लेकिन लालचंद महतो की निष्क्रियता एवं आंदोलन के प्रति गंभीर ना होने के कारण युवा वर्ग के लड़कों ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी किसी युवा नेतृत्व को देने का विचार करने लगे उसी क्रम में गोड्डा की मीटिंग में यह तय किया गया कि पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन बजरंगी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस मीटिंग के बाद साहिबगंज मछुआ सोसाइटी में मोर्चा द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें ओबीसी समाज के शिक्षाविद सामाजिक कार्यकर्ता एवं

विधायकों के बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने आनन-फानन में स्थानीय एवं नियोजन नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अमर बाउरी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बैठक के बाद मोर्चा के संयोजक बजरंगी यादव से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के बाद ओबीसी समाज के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है उनका कहना है कि यदि सरकार चाहे तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश कर आरक्षण का कोटा 50 परसेंट से ज्यादा बढ़ा सकती है और वैसी स्थिति में बिना किसी के आरक्षण कोटे को खत्म किए बिना या कम किए बिना ओबीसी समाज को हक मिल जाएगा क्योंकि 52 परसेंट आबादी होने के बाद भी पिछड़े समाज को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं।

राज्य के नौजवानों का भविष्य अंधकार में है किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा इस गंभीर मुद्दे को संजीदगी से नहीं उठाया गया और यही कारण है कि विगत 15 वर्षों से ओबीसी समाज अंदर ही अंदर अपनी हकमारी को लेकर आंदोलित हो रहा है उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि राज्य में ओबीसी का आरक्षण कितना परसेंट है बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस विसंगति को यदि दूर नहीं किया गया तो राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

उन्होंने समाज के बहुसंख्यक ओबीसी एवं अल्पसंख्यक मुसलमानों के हक का सवाल उठाते हुए यहां तक कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए उन्होंने अपने समाज को सचेत करते हुए यह भी बताया कि क्यों ना हम सभी मिलकर समाज को जागरूक करें और सरकार के अंदर पुरजोर तरीके से अपनी मांग को सामने रखें। बजरंगी यादव की बात अपनी जगह सौ प्रतिशत सही है राजनीति गुरु ने झारखंड के पहले जमीनी सर्वेक्षण में यह पाया की यदि ओबीसी समाज जागरुक होकर अपनी राजनीतिक ताकत को पहचान ले तो झारखंड की 44 विधानसभा सीटें अपने बलबूते पर जीत सकती है और फिर राज्य में आरक्षण की विसंगतियों पर ठोस कदम उठा सकती है लेकिन सर्वेक्षण में यह भी पाया गया की मूलतः जो भी सरकार है सत्ता में आई उन्होंने कभी भी ईमानदारी से इस मुद्दे पर चिंतन नहीं किया या फिर ओबीसी समाज को उनका हक कैसे मिले इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिखी। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस विसंगति को दूर करने के लिए एक उप समिति का गठन भी किया था जिसका नेतृत्व तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। उनके नेतृत्व में उपसमिति ने राज्य में आरक्षण का कोटा 71 परसेंट करने की अनुशंसा की थी। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी गई उस रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ की यदि राज्य सरकार को 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण का कोटा देना है तो उसे जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ही दे सकती है मामला न्यायालय का बताकर सरकार चुपचाप बैठ गई जबकि उस फैसले में तमिलनाडु के मामले का भी जिक्र हुआ था जो उस समय उच्चतम न्यायालय में लंबित था न्यायालय ने अपना अभिमत दिया था कि तमिलनाडु मामले के फैसले के बाद यदि राज्य सरकार चाहे तो उस फार्मूले के तहत आरक्षण का कोटा बढ़ा सकती है उसके बाद ना तो राज्य सरकार और ना ही यहां के नौकरशाहों इस मुद्दे को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई यह तो राज्य स्तर पर 14% आरक्षण की बात हो रही है यदि इसकी गंभीरता को पहचानना है तो शिड्यूल जिलों के आरक्षण रोस्टर को देखा जा सकता है जिसमें 6 ऐसे जिले हैं जहां तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण कोटा 0 है शेष जिलों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अब यह देखने वाली बात है कि जिला स्तर की नियुक्तियों की विसंगति पर आज ओबीसी समाज एक साथ खड़ा नहीं होगा तो फिर अगले 50 वर्षों तक उसे समाज के नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा इन्हीं मुद्दों को लेकर अब जमीन पर पिछड़े वर्ग का संघर्ष उतरने लगा जिसकी बानगी संथाल परगना में साफ- साफ देखी जा सकती है आजसू पार्टी के छात्र संगठन द्वारा भी इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया जा चुका है अब ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर अगले चुनाव आते-आते ओबीसी समाज अपने हक की लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है सच्चाई तो यह है कि जो लोग दलों के परिधि में बंधे हैं वह खुले तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं लेकिन जय प्रकाश वर्मा जैसे विधायक इस गंभीर मुद्दे पर प्रखर होकर बोलना शुरू किए हैं बता दें कि विगत कई सत्रों में जेवीएम के विधायक प्रदीप यादव द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग अपने हक के लिए जागरुक नहीं हैं और यही कारण है कि कोई भी सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हो पा रही है लेकिन प्रदीप यादव का कहना था कि ज्यादा समय तक इस मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता कुछ राजनीतिक विचारकों का मानना है कि ओबीसी समाज के आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि उनके आरक्षण की सीमा को घटाकर पिछड़े समाज को आरक्षण दिया जाएगा जो बिल्कुल गलत है एससी और एसटी के आरक्षण की सीमा उनके जनसंख्या के अनुपात में पूरे भारत में देने का संवैधानिक बाध्यता है ।

आदिवासी समाज में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि उनके आरक्षण की सीमा को घटाकर पिछड़े समाज को आरक्षण दिया जाएगा जो बिल्कुल गलत है।

उसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता वैसी स्थिति में ओबीसी समाज के शिक्षित लोगों को आगे आकर अपनी बात ईमानदारी से समाज में रखनी पड़ेगी और तब जाकर 52 परसेंट आबादी वाले ओबीसी समाज को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सकेगा और बिना आंदोलन अथवा संघर्ष के यह अधिकार मिल जाए ऐसा दिखता नहीं है। राजनीतिक गुरु पत्रिका की सर्वे टीम का विश्लेषण चौंकानेवाले तथ्य सामने लाए और उन तथ्यों को लगातार अपने पहले अंक से लेकर अब तक उठाया जा रहा है समाज के प्रति सजगता और जागरूकता हमारा पहला लक्ष्य है और उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है अब यह देखना है कि पिछड़े समाज का यह आंदोलन जो जमीन पर अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है वह भविष्य में कितना सफल हो पाता है।

बिहारी राजनीति की ये मर्दानियां...

ये बिहार की राजनीति की मर्दानियां हैं। हम इन्हें मर्दानी इसलिए कह रहे हैं कि अपने मुकाम के लिए इन सबने बहुत संघर्ष किया और आज भी कर रही हैं। इन्हें थाल में सजाकर कोई पद नहीं मिला। संघर्ष के हर चूल्हे -चौके को लांघकर इन्होंने सियासत की देहरी पर अपने पांव जमाए हैं। हर विषय पर इनके अपने मौलिक विचार हैं। ये गलत को गलत और सही को सही कहने का माद्दा रखती हैं। हम आनेवाले अंकों में ऐसी और भी सियासी मर्दानियों से आपको रू - ब - रू करायेंगे। इस अंक में पढ़िये चार नेत्रियों की कहानी, हमारे संवाददाता **रतन कुमार** की जुबानी...

अनामिका पासवान कहती हैं

केंद्र और बिहार में

पूंजीपतियों की सरकार

सरकार की सारी योजनाओं का निजीकरण पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, सरकार ने मात्र 5 करोड़ सालाना की आय पर लाल किले को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेक्युलर की तेजतर्रार नेत्री, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनामिका पासवान का जन्म सांसद देवानंद पासवान के घर हुआ। अनामिका पासवान बचपन से ही अपने पिता के साथ राजनीतिक सभाओं में जाया करती थीं, अपनी बेबाक अंदाज के लिए बिहार की राजनीति में वे एक जानी-मानी नेत्री हैं पटना के मलाही पकरी में दलितों की बस्ती को जब उजाड़ा गया था तब उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। अनामिका ने कहा कि दलितों, पिछड़ों के हक की लड़ाई आज कोई भी पार्टी नहीं करती है सभी केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे रहते हैं।

लेकिन केवल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी ही दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के हक की बात तो सभी करते हैं लेकिन हक देने की बात आती है तो सभी पीछे हट जाते हैं महिलाओं को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए। किसी भी चुनाव में पार्टियां महिलाओं को 15% ही टिकट देती हैं, उसमें भी ज्यादातर सांसद विधायक या दबंगों के परिवार की ही महिलाओं को टिकट दिया जाता है जबकि पार्टी से जुड़ी कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो कहती हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी आगामी चुनाव में महिलाओं को कम से कम 30% देगी, सभी पार्टियां अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दें तो महिला विधायक की जरुरत ही नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते फिर रहे हैं कि पिछले 15 सालों से जबसे वे मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में काफी विकास हुआ है वह लोगों से अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं मुख्यमंत्री को जनता की चिंता नहीं है उनके द्वारा दिखाया गया विकास का सपना झूठ का पुलिंदा है। लड़कियों के चलाए गए साइकिल योजना में काफी घोटाला हुआ है बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें साइकिल मिला ही नहीं है। आठवीं से बारहवीं की लड़कियों को लैपटॉप देने की योजना अभी तक बिहार में लागू नहीं हुई है। बिहार में शिक्षा का स्तर काफी नीचे है हर दिन शिक्षा विभाग में कोई न कोई घोटाला हो रहा है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है जब तक सरकारी स्कूलों में नेता, अफसरों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी शिक्षा में सुधार नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में वीआईपी इलाकों के इंदिरा आवास को तोड़वा कर बड़े-बड़े बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है, बिहार में शराबबंदी की पहल अच्छी है लेकिन शराब की दुकान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलवाए थे। उनके शासनकाल में ही बिहार में शराब की दुकानें ज्यादा खोली गईं। अनामिका ने कहा कि शराबबंदी कानून गलत तरीके से बनाया गया है। इस कानून के तहत केवल गरीबों को जेल भेजा जा रहा है अमीरों के घर तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। अभी तक सवा लाख गरीबों को जेल में बंद कर दिया गया है कई ऐसे थाने हैं जहां से शराब बेची जाती है यह लाइसेंसधारी गुंडे हैं। बालू बंद कर मजदूरों को भुखमरी की कगार पर ला दिया गया है पहले उसका निदान करना चाहिए था।

सृजन घोटाला मामले में सुशील मोदी और उनके परिवार के नाम आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार पूंजीपतियों की सरकार है नोटबंदी के समय गरीबों के खाते में 15 - 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में भेजने की बात की गई थी, कहां गए वो वादे। भारत सरकार की सारी योजनाओं का निजीकरण कर पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है, केंद्र सरकार ने मात्र 5 करोड़ सालाना की आय पर लाल किले को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जबकि उससे ज्यादा कमाई तो सालाना अभी ही होती थी। बिहार में अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है हर दिन हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही बहुत बढ़ गई है गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फंसाया गया है सृजन घोटाला मामले में सुशील मोदी और उनके परिवार के नाम आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दलित समाज आज कुंठित है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया उसे क्यों खंडित किया जा रहा है क्या है यह एक सोची समझी साजिश चल रही है। क्या आरक्षण को समाप्त करने की सुनियोजित कोशिश हो रही है! अनामिका पासवान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा और RSS सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

मधु मंजरी ने कहा

शिक्षा से ही होगा समाज में बदलाव

बिहार में मात्र रालोसपा ही एक ऐसी पार्टी है, जिसने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पार्टी लड़ रही है।

मधु मंजरी का जन्म एक संपन्न व्यावसायिक परिवार में पटना में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई- लिखाई में वह साधारण थी। लेकिन बचपन से ही सावित्री बाई फुले को अपना आदर्श मानने वाली मधु मंजरी का सामाजिक कार्यों में काफी रुझान था। पटना से मैट्रिक-इंटर और होम साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने स्लम बस्तियों के बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने शिवी फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के अंतर्गत आज 900 गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यह संस्था उन बच्चों को शिक्षा देती है,जो बच्चे कहीं काम करते हैं या सड़क पर रहते हैं।

पिछले 16 -17 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मधु मंजरी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करती आ रही हैं। इसके अलावा मधु मंजरी वीमेन वर्ल्ड संस्था द्वारा समाज की उपेक्षित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग कराती हैं तथा उन्हें अपना उद्योग स्थापित करने में मदद करती हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में कुछ बड़ा बदलाव करना है तो राजनीति में आना होगा।

इसीलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा । हालांकि, राजनीति में आने से कुछ लोगों ने मना भी किया कि राजनीति ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने काम के दौरान ही देखा कि बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शिक्षा को लेकर अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। मधु मंजरी ने कहा कि बिहार में मात्र रालोसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। गरीब बच्चों को उचित शिक्षा मिले इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। यह शिक्षा का अभाव ही है कि राजनेता जो बोलते हैं लोग उसे सही मान लेते हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, जो शिक्षित नहीं होने के कारण लोगों को पता ही नहीं चल पाता। गरीब शिक्षा के अभाव में उन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते और अधिकारी सारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही एक विकसित समाज बन सकता है। हम एक विकसित बिहार की कल्पना भी तभी कर सकते हैं। सूबे की राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में बिहार में जंगलराज था उस समय लोग डरे सहमे रहते थे। लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था। नीतीश कुमार की सरकार में लड़कियों को आजादी मिली है नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दूसरी बार जब नीतीश की सरकार बनी है तो वैसा काम नहीं हो सका है जैसा पहले हुआ था, धीरे-धीरे बिहार फिर से 90 के दशक की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम हो रही है। बच्चियों, महिलाओं के साथ रेप की घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, रेप की घटनाओं पर राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालते हैं और फिर उस घटना को भूला दिया जाता है। इन सबके बीच तेजी से बढ़ रही रेप की घटनाओं की मुख्य वजह पर कोई सवाल नहीं उठाता जबकि रेप का सबसे बड़ा कारण पोर्न साइट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इन पोर्न साइट्स को भारत में बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी इन साइट्स को नहीं देख पाए।

सामाजिक स्तर पर जो सबसे पिछड़ा तबका है, उसको आगे लाने के लिए आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण में कुछ संशोधन होना चाहिए।

आज छोटे-छोटे बच्चों के पास मोबाइल फोन और फ्री इंटरनेट है जिसके कारण बच्चे इन साइट्स को देख रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लड़कियों की समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अगर शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तभी दहेज प्रथा को खत्म किया जा सकता है। लड़कियों को पैतृक संपत्ति में भी बिना मांगे अधिकार होना चाहिए। कानून तो है लेकिन मिलता नहीं है इसके लिए लोगों को जागरुक करना होगा। सामाजिक स्तर पर जो सबसे पिछड़ा तबका है उसको आगे लाने के लिए आरक्षण देना चाहिए आरक्षण में कुछ संशोधन होना चाहिए। आरक्षण लोगों को आधार मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि प्रमोशन के लिए होना चाहिए।

एमएलसी रीना यादव कहती हैं

बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा

बाल विवाह, दहेज प्रथा बंदी को लेकर बिहार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। इससे समाज में व्यापक बदलाव आया है। लोगों की सोच बदली है।

जदयू से नालंदा की एमएलसी रीना यादव का जन्म पटना के बोरिंग रोड में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ । उनके पिता की पटना में प्लास्टिक के सामान की दुकान थी और उनकी माता एक बुटीक चलाती थी। उन्होंने सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। शादी हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और समाजशास्त्र से एमए किया। लालू प्रसाद के शासनकाल में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। उसी समय कुछ लोगों की मिलीभगत से उनके पिताजी की दुकान को तुड़वा दिया गया। उसके बाद उन लोगों को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1995 में मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यादव समाज में उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि लड़कियां ज्यादा पढ़ाई करेंगी तो उनकी शादी में परेशानियां होंगी।

पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने शादी में मेहंदी लगाने का काम शुरू किया। 19 साल की उम्र में 2000 में नालंदा के राजू यादव से उनकी शादी तय हो गई राजू यादव उस समय राजनीति में स्ट्रगल ही कर रहे थे पहली बार उनके पति राजू यादव नालंदा से एमएलसी का चुनाव लड़े और 35 वोट से हार गए। 2005 में हुए रीलेक्शन में हिलसा से एलजेपी से चुनाव लड़े और 12 वोटों से हार गए। 2009 में उनके पति राजू यादव ने नालंदा से नॉमिनेशन तो किया लेकिन एक साजिश के तहत उन्हें आर्म्स एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया गया। तब रीना यादव ने उनकी जगह पर चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट मांगे। 2009 में एलजेपी पार्टी से राजू यादव ने पहली बार चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 2010 में हिलसा से रीना यादव चुनाव में खड़ा हुई लेकिन 10 हजार वोट से चुनाव हार गईं। 2015 में रीना यादव जदयू से नालंदा में एमएलसी का चुनाव लड़ी और 600 वोटों से जीत दर्ज की। महिलाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ तेजी से अत्याचार बढ़ रहे हैं एक तरफ सरकार महिलाओं को जागरुक करने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के करीबियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। महिलाओं के लिए बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही है लड़कियों के लिए पोशाक राशि, नैपकिन की राशि, साइकिल योजना छात्रवृत्ति आदि कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए मेयर की सीट आरक्षित रखी गई है। महिलाओं को 35% सरकारी योजनाओं में आरक्षण दिया गया। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35% सीटें दी गईं। बिहार सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गांव में स्वयं सहायता केंद्र जीविका चलाया जा रहा है, इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिला सबल हो रही हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, शराबबंदी से महिलाएं काफी खुश हैं। यह महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने लागू किया है। बाल विवाह दहेज प्रथा बंदी को लेकर बिहार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने हमेशा से बिहार की जनता की भलाई के लिए ही काम किया है।

क्रेडिट कार्ड योजना सबके लिए है, चाहे लड़का हो या लड़की 4 लाख तक लोन मिल सकता है। महिलाओं को ध्यान में रखकर बिहार सरकार काम कर रही है लेकिन सरकार के साथ-साथ जनता को भी जागरुक होना चाहिए ,महिलाएं शिक्षित होंगी तो उन्हें सही गलत का पता रहेगा। बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। शादी में जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी उन्होंने हमेशा से बिहार की जनता की भलाई के लिए ही काम किया है।

डॉक्टर सुहेली मेहता कहती हैं

राजनीति मेरे खून में है

वैशाली के महनार में एक राजनीतिक घराने में जन्मी डॉक्टर सुहेली मेहता बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी तेज थी। मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने महनार में ही रहकर की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज से किया। उनकी मां महनार गर्ल्स हाईस्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल थीं। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और एमए की पढ़ाई पूरी की। पीएचडी उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से किया। 2003 में व्याख्याता के रूप में पहली पोस्टिंग पटना विमेंस कॉलेज में हुई उसके बाद पटना मगध महिला कॉलेज में पोस्टिंग हुई। उनके पिता तुलसीदास मेहता बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं तुलसीदास मेहता बिहार की राजनीति में काफी चर्चित नेताओं में से एक हैं, वह 1962 से 2000 तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। उस दौरान वे कई बार बिहार सरकार में अलग-अलग विभागों के मंत्री बने। डॉ सुहेली मेहता का मानना है कि लड़कियों को समाज में आगे लाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरुरत है। इसलिए उन्होंने लड़कियों को खेल में प्रोत्साहित किया। आज वह मगध महिला कॉलेज के स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर के रूप में भी काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनके पास पैसा हो या न हो अगर उनमें क्षमता है तो वह अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना सकती हैं। आज खेल के माध्यम से कई लड़कियों ने अपना और देश का नाम रोशन किया है। बिहार की लड़कियां भी खेल के क्षेत्र में अपना पहचान बना सकती हैं।

लेकिन उन्हें मदद करना जरूरी है। कई बार लड़कियों को परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है जिसके कारण उनकी क्षमता दब जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर जो लड़कियां खेलती हैं। कई बार उनके परिवार बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं ऐसी परिस्थिति में उन्हें उनके परिवार के लोगों को समझाना पड़ता है । लड़कियों को स्कूल, कॉलेज में एक मेंटर की जरूरत है। जो लड़कियों को खेल में बढ़ावा दे। बिहार सरकार को खेल के लिए ब्लॉक लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्टर मजबूत करना चाहिए।

देश और राज्य की सियासत पर बात करते हुए वह कहती हैं कि राजनीति उनके खून में है। पढ़ाने का काम उन्होंने सामाजिक सेवा के रूप में अपनाया है। पर राजनीति की प्रेरणा उन्हें परिवार से ही मिली है। हमेशा से समाज सेवा करना उन्हें अच्छा लगता है। राजनीति में पिछले 5 सालों से सक्रिय भूमिका निभा रही डॉ सुहेली मेहता कहती हैं, राजनीति को मैं समाज सेवा के रूप में मानती हूं, कैरियर के रूप में राजनीति को नहीं मानती। पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में आना जरूरी है। उन्हें लगता है कि जब कभी राजनीति में कुछ गलत होता है, उसका विरोध करने के लिए पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए । उन्होंने 2013 से राजनीति की शुरुआत भाजपा से की थी 2015 के उप चुनाव में एनडीए से चुनाव भी लड़ी। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा । 2017 से जदयू में शामिल हुई। सीएम नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहती हैं कि बिहार में शराब बंदी होने से घरेलू हिंसा बहुत कम हुई है । सरकार महिलाओं को बराबर का दर्जा तो देना चाहती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण उच्च पदों पर बैठे पुरुषों को लगता है कि महिलाएं ठीक से काम नहीं कर पाएंगी यही कारण है कि महिलाएं राजनीति में आज काफी कम हैं। महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण राज्यसभा से पारित हो चुका है उसे केंद्र सरकार लोकसभा से भी पारित करे तो राजनीति की दिशा बदल जाएगी। आज राजनीतिक दल कहीं भी टिकट देते वक्त सबसे पहले जातीय समीकरण को देखते हैं बिहार की राजनीतिक पार्टियां जाति के दम पर ही राजनीति करती हैं बिहार के लोगों को जागना होगा तभी राजनीति में सुधार हो सकता है। लोगों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट देना चाहिए। बिहार ही ऐसा पहला राज्य है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने स्थानीय निकाय और पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया।

> बिहार की लड़कियों में खेल की अधिक क्षमता है। जरूरी है उनका साथ देने की । कई बार लड़कियों को परिवार से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उनकी क्षमता दब जाती है यूनिर्विसटी लेवल की जो लड़कियां खेलती हैं ।

इससे महिलाओं में काफी परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांत की राजनीति करते हैं। जनता के लिए सात निश्चय का जो निर्णय लिया है, उस पर काम कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देश में सभी पार्टियां दलितों की बात कर रही हैं दलितों के लिए आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां दलितों को भ्रमित कर रही हैं। बिहार के शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार नौकरी करने वाले सभी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर दे, तो शिक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार हो जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्टर होने के बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं रहता है। अधिकारी जिनके ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी रहती है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं इसलिए अधिकारी सिर्फ आंकड़ों के रिकॉर्ड देने और लेने तक सीमित रहते हैं और जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान नहीं देते उन्हें बच्चों की पढ़ाई या व्यक्तित्व विकास से कोई मतलब नहीं रहता है।

● मिथिलेश कुमार पाठक

इन युवाओं से बिहार को उम्मीद

राजनीति में हर दौर में युवाओं का अपना खास योगदान रहा है, उन्होंने देश में सियासत को नई दिशा दी है। उनके आंदोलनों और संघर्ष की कई कहानियां हैं। जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। आज के दौर में भी इन युवाओं ने देश और राज्य की राजनीति को अपने सोच और जज्बे से काफी हद तक प्रभावित किया है। देश और समाज के लिए कुछ करने की उनकी चाहत ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। ऐसे ही कई चेहरों ने बिहार की राजनीति में अपनी बेबाक और जूझारू छवि की बदौलत अलग पहचान बनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि आनेवाले दिनों में ये युवा बिहार की दशा और दिशा तय करेंगे। बिहार के राजनीति की पटकथा लिखेंगे, युवा पीढ़ी की प्रेरणास्त्रोत बनेंगे। आइए, बात करते हैं ऐसे ही कुछ युवा राजनीतिज्ञों से।

राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नीरज यादव कहते हैं

कटाव पीड़ितों से किया वादा हर हाल में पूरा करूंगा...

कटिहार के बरारी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बने नीरज यादव की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती-किसानी की रही है, इनके परिवार में आमदनी का एक साधन कृषि ही रहा है। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहने के चलते आगे भी ये राजनीति में ही रहे। कटिहार के केबीएम कॉलेज से बीए करने के बाद नीरज यादव ने अपने आपको समाजसेवा में समर्पित कर दिया।

आस पास के इलाके में होने वाली सामाजिक घटनाओं ने इन्हें समाज सेवा में आने को मजबूर कर दिया। समाज में जाति-पात एवं असमानता के भेदभाव ने इन्हें झकझोर कर रख दिया। युवा एवं शिक्षित नीरज ने जब समाज में इस तरह की व्यवस्था को देखा तो इन्हें लगा की भेदभाव से समाज में कभी समानता नहीं आ सकती है।

इसलिए लोगों के बीच रहकर और लगातार प्रयास से ही समाज में व्याप्त इस कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक समरसता और जन कल्याण की भावना ने इन्हें राजनीति में आने को मजबूर कर दिया। फिर इन्होंने अपने परिवार की पारंपरिक कृषि को छोड़कर खुद को राजनीति के माध्यम से समाजसेवा में समर्पित कर दिया। अपनी राजनीति की शुरुआत इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से की। वर्षों राजद कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के संदेशों को पहुंचाने का काम किया। साथ ही पार्टी के माध्यम से क्षेत्र की जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। पार्टी ने इनकी कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें अपना उम्मीदवार बरारी विधानसभा से बनाया जहां इनकी टक्कर भाजपा के दो बार से लगातार इस सीट से विधायक रहे विभाषचंद्र चौधरी से हुई। इस चुनाव में क्षेत्र की जनता ने भाजपा उम्मीदवार विभाष चन्द्र चौधरी को नकारते हुए नीरज को विजयी बनाया। जीत के बाद इन्होंने क्षेत्र की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने में जुट गए। उन्होंने कहा कि हर साल क्षेत्र की जनता को बाढ़ और कटाव की मार झेलनी पड़ती है उसके स्थाई निराकरण के लिए प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता की जनता से मैंने जो वादा किया था वह पूरा न कर पाऊं। उन्होंने बताया कि आनेवाले समय में इस पिछड़े इलाके के लोगों के लिए शिक्षा-स्वास्थ्य सड़क, बिजली और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश करता रहूंगा। श्री नीरज का कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। विधायक बनने के बाद से क्षेत्र की जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहने वाले नीरज का कहना है कि जनप्रतिनिधि वही सफल होता है जो आमजन और क्षेत्र की जनता के बीच सर्वसुलभ हो। जनता की लगातार सेवा को अपने राजनीतिक जीवन का मूलमंत्र मानकर जनता की सेवा निरंतर करते रहना ही मेरी राजनीति का उदेश्य है।

> सालों तक राजद कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के संदेशों को पहुंचाने का काम किया। यह कोशिश की कि आम लोग अपने अधिकार को समझें, उसके लिए संघर्ष करें।

अभिमन्यु सेना के संस्थापक अभिमन्यु यादव कहते हैं

बैशाखी के बल पर लंबा नहीं होता सियासी सफर

अभिमन्यु यादव महाभारत के अभिमन्यु भले नहीं हैं लेकिन युवा सोच के अभिमन्यु अवश्य नजर आते हैं। 14 जून 1993 को पटना में जन्मे अभिमन्यु ने प्रारंभिक पढ़ाई डीपीएस नोएडा से करने के बाद उच्च शिक्षा दिल्ली के सत्यवती कॉलेज से राजनीतिशास्त्र में किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक होने की वजह से राजनीति को ही अपना कैरियर मान वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के समय से राजनीति में सक्रिय हुए इस चुनाव में इनके पिता रामकृपाल यादव राजद छोड़ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते।

अभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है फिर भी संपूर्ण बिहार में इनके चाहनेवाले युवाओं ने तथाकथित अभिमन्यु सेना नाम देकर हर जिला में युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जोर रखा है।

आनेवाले दिनों में हो सकता है कि लोगों खासकर युवाओं की मांग और सहयोग को देखते हुए इसी नाम से संगठन भी बना लें। अपने पिता की राह पर चल पड़े अभिमन्यु सर्वसुलभ और सामाजिक कार्यों में अपने आपको सदैव संलग्न रखते हैं। जो भी युवा या व्यक्ति इनके पास आता है किसी को निराश नहीं करते हैं। यथासंभव उनकी समस्या का समाधान करते हैं। अपने पिता के सहयोग से दिल्ली में कई युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध करवा चुके हैं। इनका मानना है कि सामाजिक सरोकार के तहत मुझसे जो भी लोगों की अपेक्षा होगी उसे यथासंभव करने का प्रयास करूंगा। राजनीति में अपने पिता को आदर्श मानते हुए उन्हीं की राह चलने की वकालत करते हुए इनका कहना है कि जिस तरह मेरे पिता हर तबके के लिए सर्वसुलभ रहे हैं, मैं भी उसी राह पर चलने का प्रयास करते हुए आमलोगों की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान की कोशिश करूंगा। अभिमन्यु का मानना है कि पिता की राह का अनुसरण के अलावे राजनीति में मैं अपनी कर्मठता के बदौलत खुद की पहचान बनाने का प्रयास भी करूंगा।

> आज के दौर में राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के अलावा शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना भी राजनीति का मकसद होना चाहिए।

पिता का नाम तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जीवन पर्यंत चलता है मेरे साथ भी चलता रहेगा। यह सत्य है कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है, जिस वजह से पहचान बनाने में मुझे इसका लाभ अवश्य मिला है परंतु अगर काबिलियत नहीं होगी तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, वैशाखी के बलपर कोई भी राजनीति का सफर ज्यादा तय नहीं कर सकता है। राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के अलावा शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना ही राजनीति में आने का एक मात्र लक्ष्य है।

आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद कहते हैं

पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा

युवा क्षत्रप चेतन आनंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके माता-पिता दोनों सांसद रह चुके हैं। इनकी माता लवली आनंद और पिता आनंद मोहन हैं। जब इनका जन्म हुआ उस वक्त बिहार में राजनीतिक लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों के बीच चरम पर थी, जिसका खामियाजा इन्हें अपने जन्म से ही भुगतना पड़ा। बिहार के राजनीतिक माहौल को देखते हुए पिता आनंद मोहन सिंह ने इन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए देहरादून के वेलहम ब्वायज स्कूल में नामांकन कराया, यहां से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद स्नातक कम्यूनिकेशंस एण्ड ग्राफिक्स डिजायन सिम्बोसिस स्कूल ऑफ डिजायन पुणे से किया। पेंटिंग और शूटिंग के शौकीन चेतन को उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल रहीं मार्गेट अल्वा पुरस्कृत कर चुकी हैं। शूटिंग का प्रशिक्षण इन्होंने देश के महान निशानेबाज जसपाल राणा के पिता द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य पिता आनंद मोहन सिंह को जिस साजिश के तहत फंसाया गया है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखने के बारे में अपने पिता की तरह ही जोशिले शब्दों में कहते हैं। मेरी विरासत संघर्षवाद की है वंशवाद की नहीं, शोषण विषमता और जुल्म के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखना ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य बताते हैं। पिता के राजनीतिक कदमों पर चलने का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस तरह मेरे पिता ने राजनीति अपनी शर्तों पर करते हुए कभी स्वाभिमान और सिद्धांत से समझौता नहीं किया उसी क्रम को मैं भी जारी रखूंगा। पिता द्वारा संस्थापित संगठन फ्रेंड्स ऑफ आनंद के माध्यम से आमजनों के बीच अपनी पहचान लगातार बढ़ाते हुए इस संगठन से युवाओं को जोड़ने में लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। राजनीति और संगठन के माध्यम से समाज और प्रदेश की भलाई के लिए लगातार आम जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं। जब ये किसी कार्यक्रम या लोगों के दुःख या खुशी में शामिल होने जाते हैं तो आमजन इनमें इनके पिता की छवि देखते हैं। कोसी की जनता इन्हें भविष्य का आनंद मोहन के तौर पर देख रही है। जनता का मानना है कि अपने पिता की तरह ही चेतन भी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अपने कार्यक्रम में लगातार गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग ने इन्हें सवर्णों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है। अन्य वर्गों को पूर्व से देय आरक्षण को जारी रखते हुए सरकार को गरीब सवर्णों को आरक्षण की मांग को काफी शिद्दत से उठाते आ रहे हैं। इनका मानना है कि बिहार में अगर पूर्व में जंगल राज था तो वर्तमान में अमंगल राज है। अपने पिता की सम्मानजनक रिहाई की मांग लगातार फ्रेंड्स ऑफ आनंद के माध्यम से करते आ रहे हैं इस मांग को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी करते रहे हैं। दार्शनिक अंदाज में भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं वंशवाद और संघर्षवाद में बुनियादी फर्क है जो राजनेता सत्ता या पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए अपने पुत्र या परिजन को बतौर राजनीतिक उत्तराधिकारी जनता पर थोपता है वो वंशवाद है परंतु जब कोई युवा अन्याय के विरुद्ध बगावत का परचम थामता है उसे संघर्षवाद की राजनीति कहते हैं।

> चेतन बताते हैं कि उनकी विरासत संघर्षवाद की है, वंशवाद की नहीं, शोषण विषमता और जुल्म के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखना ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य है।

कांग्रेस नेता कुमार आशीष कहते हैं

पार्टी ने टिकट दिया तो बांकीपुर से लड़ूंगा चुनाव

कुमार आशीष ने 1995 में एनएसयूआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और इसी वर्ष मगध विश्वविद्यालय एनएसयूआई के अध्यक्ष बने। 1995-96 में निजी स्कूल और कोचिंग के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इनका मानना है कि राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद यूथ कांग्रेस में चुनावी पद्धति की शुरुआत की गयी। श्री कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा पटना के लोयला स्कूल से प्राप्त करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। श्री कुमार विगत पांच वर्षों से अधिक समय से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें पटना के बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जिसमें पराजित होने के बावजूद आमलोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। इनका मानना है कि बिहार प्रदेश में यूथ कांग्रेस ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो युवाओं की लड़ाई के साथ ही आम आवाम के हक की लड़ाई सदैव लड़ता रहा है। उन्होंने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश का दौरा किया। अपने संघर्ष और जूझारूपन के दम पर इन्होंने राजधानी पटना से औरंगाबाद के देव तक लगभग 282 किलोमीटर की पदयात्रा की। बिहार के युवा एवं आमलोगों के मुद्दों के अलावे राज्य सरकार के युवा विरोधी नीतियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमिटी में प्रवक्ता सचिव के अलावे मगध विश्वविद्यालय में सिनेटर भी रह चुके हैं।

बिहार में युवाओं को जो शक्ति मिलना चाहिए वो शक्ति राज्य के किसी भी राजनेताओं द्वारा प्रदान नहीं किया गया। राज्य में बड़े नेता पुत्र जरूर चर्चित हुए परंतु आम कार्यकर्ता से नेता बनने की कोशिश कर रहे साधारण कार्यकर्ता अपनी पहचान, अपवाद छोड़कर नहीं बना सके परंतु कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी की सोच के बदौलत ही कुमार आशीष जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ताकत देने का कार्य किया उन्हीं के बदौलत ही कुमार आशीष राजनीति में अपनी पहचान बना पाये हैं।

आगे की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेवारी दी जायेगी उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने कि कोशिश करुंगा। 2020 में होनेवाले बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के बांकीपुर विधसभा सीट से लड़ने का प्रयास करुंगा वैसे यह पार्टी पर निर्भर करेगा की वह मुझे बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है या नहीं। पार्टी जो भी फैसला करेगी एक कार्यकर्ता के नाते उसे स्वीकार करुंगा क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है।

> आशीष कहते हैं कि 2020 में होनेवाले बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के बांकीपुर विधासभा सीट से लड़ने का प्रयास करुंगा। वैसे यह पार्टी पर निर्भर करेगा कि वह मुझे बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है या नहीं। पार्टी जो भी फैसला करेगी एक कार्यकर्ता के नाते उसे स्वीकार करुंगा क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। मैंने एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के हर आदेश का पालन किया है। नौजवानों को कांग्रेस के विचारों से जोड़ा है, जिसके परिणाम मिलेंगे।

बिहार में समन्वय का जनाजा, चेहरे की लड़ाई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के साथ वे बहुत आगे तक तभी चल पाएंगे, जब उनकी अपनी पार्टी मजबूत होगी, उनका अपना कद बिहार में बड़ा होगा। इसलिए वह अभी से ही सीटों के बंटवारे को लेकर सजग हो गए हैं और इसके लिए सियासी दांव भी खेल रहे हैं। लड़ाई अब चेहरे की है।

मिशन 2019 के पहले चार लोकसभा और दस विधानसभा सीटों के नतीजे आने के बाद एनडीए के सहयोगियों ने बीजेपी नेतृत्व पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। सहयोगी दलों ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बिहार में एनडीए के सभी दलों ने भी अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी पुरानी मांग को एक बार फिर से उठाना शुरू कर दिया।

जदयू की कोशिश क्या है और वह बीजेपी से क्या चाहता है ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन वर्मा ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जदयू की लड़ाई जारी रहेगी। उधर, नीतीश कुमार ने असम में बीजेपी के नागरिकता संशोधन बिल का भी विरोध कर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं, उन्होंने नोटबंदी का विरोध कर भी जता दिया है कि बीजेपी से वे कोई खास खुश नहीं चल रहे हैं। जानकारों की मानें तो नीतीश कुमार बीजेपी को एक तरह से यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार से टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एनडीए के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए वह जदयू भी कर सकता है। ये सब जानते हुए कि 14वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा केवल विशेष परिस्थिति में ही दिया जाना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दबाव इसलिए बना रहे हैं 2019 में उनकी पार्टी को बिहार कम से कम 15 लोकसभा सीटें मिलें। उधर, बिहार में एनडीए की एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाए।

उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान देकर बीजेपी नेतृत्व के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति के तहत ये घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी रालोसपा मध्य प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ेगी। जदयू से बाहर आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पूरी राजनीति नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ रही है। इसलिए राजद को छोड़ बिहार में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को अपने नए मंत्रिमंडल में जगह दी थी, लेकिन एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के किसी भी विधायक को मंत्री मंडल में जगह नहीं दी। तब से उपेंद्र कुशवाहा अपना अपमान सह कर भी एनडीए में सिर्फ. इसलिए बने हुए थे कि वे एनडीए से बाहर जाने का सही वक़्त का इंतजार कर रहे थे। उपचुनावों के नतीजों के साथ ही उन्होंने एनडीए से बाहर जाने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। वह ये अच्छी तरह से जानते हैं नीतीश कुमार के एनडीए में उनकी दाल ज्यादा गलने वाली नहीं है। वैसे भी पिछले दिनों उनके 'शिक्षा सुधार संकल्प महासम्मेलन' के मंच पर राजद नेता नज़र आते रहे हैं।

रामविलास पासवान भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे मौके पर वे बीजेपी पर दबाव बनाने में अपने सहयोगियों से कैसे पीछे रह सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान, अपने दो भाइयों रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस के साथ ताजा हालात पर मंथन किया। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पसवान ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर एसटी, एससी एक्ट और प्रमोशन में आरक्षण संबंधी बिल को जल्दी लाने की मांग की। रामविलास पासवान ने भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की नीतीश कुमार की मांग को जायज.ठहराया है।

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की बढ़ती नजदीकियां बीजेपी के लिए आने वाले समय में बड़ी परेशानी आने के संकेत हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक ही झटके में पासवान जाति को महादलित में शामिल कर बिहार की जातिगत राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। यही कारण है कि आज नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बीजेपी के खिलाफ हर क़दम पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं।

नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के लिए बीजेपी के नेता कहते रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं और पासवान किसी के नहीं सत्ता के साथ हैं। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह के लिए 2019 के चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाना तो दूर की बात है, उसे संभालना मुश्किल हो चला है।

नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के लिए बीजेपी के नेता कहते रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं और पासवान किसी के नहीं सत्ता के साथ हैं। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह के लिए 2019 के चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाना तो दूर की बात है उसे संभालना मुश्किल हो चला है। वैसे भी एक पुरानी कहावत है, राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन राजनीति के जानकार कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी मजबूरियों और जरूरतों के हिसाब से तय होती है।

हालांकि इन सब के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके बड़े भाई हैं। इसका मतलब ये है कि बिहार में गठबंधन में जेडीयू का रोल बड़ा होगा, उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बीजेपी-जदयू और लोजपा का गठबंधन चाहते हैं।

इसलिए बिहार में जो वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के काम और नाम पर, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सुशील कुमार की मानें तो दोनों पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है।

वहीं, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा है कि जब दिल मिल गया है तो सीट कौन-सी बड़ी चीज है। हर चुनाव के अंदर कौन कितना लड़ेगा, जिस दिन साथ बैठेंगे सारी चीजों का ऐलान हो जाएगा। बहरहाल, पटना के सियासी गलियारों में यह चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि नीतीश के बदले रुख से बीजेपी बेचैन हो गई है। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी का बयान यूं ही नहीं आया है बल्कि इसके पीछे भी अंदर ही अंदर चल रही खींचतान जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है।

इसको लेकर लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लंबी बातचीत की है और बिहार की सियासत पर बात भी की है। इस दौरान एनडीए के बीच की संवादहीनता खत्म करने पर भी बात हुई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने रामविलास पासवान को ही नीतीश कुमार से बात करने का जिम्मा सौंपा। वहीं बताया जा रहा है कि सारे विवाद की जड़ जदयू का सबसे अधिक सीटें मांगने से शुरू हुआ है। कहा जा रहा है कि एनडीए का सबसे बड़ा घटक होने के चलते जदयू सबसे अधिक सीटें चाहता है। जदयू का तर्क है कि भाजपा अपने कोटे से लोजपा और रालोसपा को सीटें दे। अगर ऐसा होगा तो लोजपा और रालोसपा की सीटें कम होंगी, जो शायद इन दलों को मंजूर ना हो।

वहीं जदयू के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पार्टी नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का चेहरा बनाने को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि इस बीच लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए का चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इससे एक बार फिर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार सहित पूरे देश में जो स्थिति बनी है उससे भाजपा भी बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। एनडीए के कुनबे में किसी प्रकार की कोई फूट न हो इसके लिए भाजपा अध्यक्ष खुद सभी सहयोगी से बातचीत करने की कोशिश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार महागठबंधन की ओर से एक मंच पर आकर भाजपा को टक्कर देने की कोशिश हो रही है उससे कहीं न कहीं पार्टी के अंदर यह जोरशोर से चर्चा हो रही है कि अगर ऐसे समय में एनडीए के पार्टनर साथ छोड़ेंगे तो आम जनता मे संदेश तो गलत जाएगा ही साथ ही जिस प्रकार हर राज्य में जातीय समीकरण को साधते हुए सहयोगी दलों के साथ गठबंधन हुआ था वह भी कमजोर हो जाएगा।

जदयू के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पार्टी नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का चेहरा बनाने को लेकर अड़ी हुई है।

भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह नहीं चाहता कि ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है किसी भी सहयोगी का साथ छूटे और फिर से एक नए सहयोगी की तलाश की जाए। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इससे एक ओर तो जनता के बीच विश्वनियता की कमी होगी वहीं दूसरी ओर नए सहयोगियों का क्या रुख होगा ये नए सिरे से समझना होगा। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है और जनता के समक्ष मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को रखा जा रहा है। इसलिए अब इसका वक्त नहीं है कि एक बार फिर से नए सहयोगी की तलाश की जाए।

पॉलिटिकल पिच पर छा गए तेजस्वी

बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाती जा रही है, सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। हर दिन एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच उपचुनाव में मिली जीत से राज्य का मुख्य विपक्षी दल राजद गदगद है। इसके पीछे सिर्फ उपचुनाव की खुशी नहीं है बल्कि राजद के दिग्गजों की मानें तो इस जीत में जो सबसे बड़ी बात उभरकर सामने आयी है वह है तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता, उनके नेतृत्व पर जनता ने मुहर लगा दी है। कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब पूरे परिवार पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं परिवार के मुखिया लालू यादव एक मामले में सजा काट रहे हैं। तेजस्वी यादव का किसी परिपक्व नेता की भांति हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखना पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक सबों को लुभा गया। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो लालू की अनुपस्थिति में तेजस्वी ने अपने दम पर एक लोकसभा और दो विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलायी है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की सियासी आसमान में एक नए सितारे का उदय हो गया।

तेजस्वी क्रिकेटर रहे हैं इसलिए उनका कुछ मिजाज भी उसी तरह का पॉलिटिकल पीच पर भी नजर आता है वे अपने विपक्ष को सोचने-समझने का मौका नहीं देते। वे एक अटैक करने में विश्वास करते हैं डिफेंसिव बिलकुल नहीं होते। सामने वाले को हमेशा दबाव में रखते हैं ताकि वह अपनी स्ट्रैटजी पर ज्यादा सोच ही नहीं पाए। जानकारों की मानें तो बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री पर वे अक्सर ट्विटर के जरिए अटैक करते रहते हैं। कोई भी दांव खाली नहीं जाने देते जिससे सत्ताधारी पार्टियों की मुश्किलें बढती जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अपने पिता लालू से बिलकुल उलट तेजस्वी का तेवर गंभीर है। इसीलिए लालू ने अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी है।

इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जिसप्रकार की शुरुआत उन्होंने की है उसने लालू यादव को चिंतामुक्त जरूर कर दिया होगा। तेजस्वी ने अपने स्ट्रैटजी और सोच से न सिर्फ अपने पिता लालू यादव की उम्मीद पूरी की है बल्कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सुझबूझ से रणनीतिक फैसले कर उन्हें भी अपनी कार्यशैली का मुरीद बना लिया है। राजद के वोटबैंक एमवाई को सुरक्षित रखते हुए जिस प्रकार वे तेजी से युवाओं के बीच अपनी अलग छवि गढ.रहे हैं उससे आने वाले दिनों में राजद का जनाधार बढ़ना तय है।

देखा जाय तो तेजस्वी यादव के प्रति जिस प्रकार बिहार में महौल बन रहा है उससे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल को लाभ होना तय है। अन्य विपक्षी दलों के नेता भी तेजस्वी की युवाओं में बढती लोकप्रियता के मुरीद होते जा रहे हैं। जानकारों की मानें तो जिस प्रकार 2015 के बाद तेजस्वी यादव ने सियासत में खुद को निखारा है उससे उनकी छवि एक गंभीर और जूझारू नेता रूप में उभर कर सामने आयी है।

इसके प्रमाण उनके द्वारा सदन में दिए गए भाषण से भी झलकते हैं। सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार के मुद्दों को वे जिस प्रकार पेश करते हैं उससे राज्य की जनता का विश्वास उन पर जमता दिखता है। अपनी बेबाकी से उन्होंने सत्तापक्ष को लगातार असहज कर दिया है। सदन के बाहर तो उन्होंने जिस प्रकार सरकार के फैसलों को लेकर जनता के बीच लड़ाई लड़ी है, उससे जदयू और बीजेपी के नेताओं में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी लगातार सक्रिय रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित किसी भी शख्सियत को निशाना बनाने से नहीं चुकते।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो उनकी आक्रमक राजनीति के कारण ही आज वे देश के स्तर पर भी अपना अलग प्रभाव बना पाए हैं। यही वजह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। देश के दिग्गजों के बीच खड़े होकर उन्होंने अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू यादव की कमी नहीं खलने दी। वैसे देश के सभी युवा नेताओं के बीच भी उनकी खास दोस्ती के चर्चे अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ लंच की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब चिर्चत हुई थीं। इस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया था, 'लंच के लिए शुक्रिया राहुल। आपने व्यस्तताओं के बीच भी लंच के लिए समय निकाला इसके लिए शुक्रिया।'

तेजस्वी द्वारा पार्टी हित में उठाए गए कदमों की तारीफ भी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं की वे आने वाले दिनों में देश की राजनीति का प्रमुख चेहरा होंगे। यही कारण है कि वह विपक्षी नेताओं के चहेते भी बनते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि बिहार में एनडीए को चुनौती देना है तो राजद को साथ रखना जरूरी है और इसके लिए लालू के नहीं रहने पर तेजस्वी ही यह काम कर सकते हैं। कांग्रेस ममता बनर्जी, अखिलेश यादव आदि भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ को एकजुट करना चाहती है, जिसका सीधा निशाना मिशन 2019 है।

जानकारों की मानें तो लालू यादव ने बहुत ही सोच-समझकर तेजस्वी को राजद की कमान सौंपी है। वे जानते हैं कि तेजस्वी तेजतर्रार हैं, गंभीर हैं। बिहार और देश के ज्वलंत मुद्दों पर उनकी स्पष्ट सोच हैं और अपनी बात पूरी बेबाकी से पूरी निडरता से रखते हैं। इन सबके साथ ही युवा हैं जिसकी आबादी

पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सुझबूझ से रणनीतिक फैसले कर उन्हें भी अपनी कार्यशैली का मुरीद बना लिया है।

भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघन सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव राजनीति के क्षेत्र में बहुत तेजी से अपनी पैठ बिहार की जनता के बीच बना रहे हैं। राजनीति में बहुत ही जल्दी तेजस्वी यादव परिपक्क हुए हैं।

आज बिहार में सबसे ज्यादा है। नई पीढी के साथ तालमेल बनाकर चलने की जरुरत को भांपते हुए लालू यादव ने तेजस्वी को राजनीति के वैसे सभी गुर भी सिखाए हैं जिससे वे अपने प्रतिद्वंदियों को मात दे सकें।

अब धीरे-धीरे पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर स्वीकार्यता होने लगी है कि तेजस्वी राजद को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कई बार कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सियासी हलकों में कई बार इस तरह की चर्चा हुई कि तेजस्वी के कार्यशैली से वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है और लालू के नहीं रहने से आगे आने वाले दिनों में पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं इस मामले को विपक्षी दलों जदयू और बीजेपी ने भी खूब हवा देने की कोशिश की पर बाद में मामला शांत हो गया।

देखा जाय तो जिस प्रकार देश में बीजेपी तेजी से बढ.रही है वह कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष को एक मंच पर आना जरूरी हो गया है। ऐसे में एक बार फिर क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ. गई है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां एनडीए के खिलाफ राजद के नेतृत्व में विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद-जदयू गठबंधन ने बीजेपी को हराकर कर यह साबित भी कर दिया था।

बहरहाल, तेजस्वी की लोकप्रियता तो राजद में बढी है ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उनकी परिपक्क्ता को माना है और स्वीकार किया है कि तेजस्वी देश की राजनीति का चेहरा बनने की पूरी काबलियत रखते हैं।

भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघन सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव राजनीति के क्षेत्र में बहुत तेजी से अपनी पैठ बिहार की जनता के बीच बना रहे हैं। राजनीति में बहुत ही जल्दी तेजस्वी यादव परिपक्कहुए हैं। उनमें समझ है। उन्हें बिहार की जनता की समस्याओं का पता है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव केवल आज का ही नहीं बल्कि कल का भी चेहरा हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं। इतना ही नहीं शत्रुध्न सिन्हा ने तेजस्वी को राजनीति का अर्जुन बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में विकास के कामों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि एनडीए तेजी से काम करे नहीं तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव उनकी जगह लेंगे। वहीं, लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार की सियासत के प्रमुख चेहरा होंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान को भी बिहार का भविष्य का लीडर बताया लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि तेजस्वी ने अपने दम पर उपचुनावों में राजद को जीत दिलाई है उससे उनकी दमदार छवि उभरकर सामने आई है।

बोरियो live

क्षेत्र में लड़ाई बड़ी कठिन है भाई !

बोरियो सीट पर भाजपा और झामुमो के बाद फिलहाल किसी तीसरे दल की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। लोबिन हेम्ब्रम भी एक फैक्टर हैं।

मनोज कुमार सिंह

सिदो -कान्हू की पवित्र धरती भोगनाडीह के करीब से शुरू हो रहे बोरियो विधानसभा मूलतः आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बोरियो विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व का मौका जनता ने लोबिन हेंब्रम को दिया है। लोबिन हेंब्रम वस्तुतः जमीनी नेता हैं और गांव देहात के लोग उनकी शैली और व्यवहार को बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक बार टिकट कट जाने के बाद भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया था कि इस विधानसभा में उनकी पकड़ किस स्तर की है वैसे समय-समय पर बोरियो के मतदाताओं ने उनके कार्यशैली को सुधारने की नीयत से चुनाव हरवाया भी है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ताला मरांडी ने बहुत मशक्कत के बाद लोबिन हेंब्रम को 503 मतों से पराजित किया। बोरियो विधानसभा के तीन प्रखंड बोरियो, वोआरि जोर एवं मंडरो भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से अलग अलग स्वरुप में दिखते हैं।

आदिवासी यानी संथाल जाति में बहुत पहले से ही झामुमो के प्रति लगाव रहा है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जलवा पूरे संथाल समाज पर साफ-साफ दिखाई देता है। वैसे जेवीएम ने क्षेत्र के बाहुबली सूर्या हासदा को अपना उम्मीदवार बनाकर भय के बल पर झामुमो के वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन वह विफल हो गया। भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में शुरू की थी लेकिन उन्हें भी यह एहसास हो गया कि इस क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतना नामुमकिन है। अब बोरियो विधानसभा की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा और झामुमो आमने-सामने चुनाव में अपना ताल ठोकेंगे। किसी तीसरे दल की कोई गुंजाइश फिलहाल तो नहीं दिखती।

आदिवासी क्षेत्रों में हटिया राजनीतिक एवं सामाजिक तस्वीर को बयां करती है ,शनिवार के दिन बोरियो में बृहद हटिया लगता है- चलते-चलते हटिया में युवा नेता रमेश हांसदा से मुलाकात हो जाती है। मैंने जब उनसे आगामी चुनाव से संबंधित प्रश्न किया तो उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि बोरियो में लोबिन बाबू के आगे किसी की दाल नहीं गलेगी।

राजनीतिक जानकार होने के नाते उन्होंने यह भी बताया की विगत चुनाव में हार के कारणों में पहाड़िया जनजाति का एकमुश्त वोट भाजपा को मिलना बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार की स्थिति बिल्कुल विपरीत है महागठबंधन बनने के कारण आदिवासी- मुस्लिम मतदाताओं की एकता चुनाव में नया रंग भरेगी।

पिछले चुनाव में हिंदू मतदाताओं की नाराजगी लोबिन हेंब्रम से थी जो इस बार नहीं दिखती है। झामुमो के पुराने कार्यकर्ता संजय राय से मुलाकात हटिया के पान दुकान पर हो गई ,वह अपना दर्द इस रूप में बयां कर रहे थे कि विगत चुनाव में बहुत से पुराने हिंदू कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया, उनकी नाराजगी अब खत्म हो गई है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लोबिन दा के लिए जी जान लगा कर जिताने का काम करेंगे।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जलवा पूरे संथाल समाज पर साफ–साफ दिखाई देता है। वैसे जेवीएम ने क्षेत्र के बाहुबली सूर्या हांसदा को अपना उम्मीदवार बनाकर भय के बल पर झामुमो के वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन वह विफल हो गया।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

श्री राय ने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता को लोबिन हेंब्रम के संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते हैं उनकी सर्व सुलभता ही उनकी पहचान है और कभी भी अपने व्यवहार में उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया।

भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह जो विगत चुनाव में ताला मरांडी के सारथी थे , हालांकि वर्तमान में विधायक के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं चल रही है। अपने चुनावी रणनीति के आधार पर उन्होंने जो खाका खींचा था वैसी रणनीति बनाने वाला कोई दूसरा कार्यकर्ता दिख तो नहीं रहा है।

इस सच्चाई को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हैं। बोरियो बाजार के राम प्रसाद भगत ने यह बताया कि वर्तमान विधायक और संगठन के बीच तालमेल की कमी साफ-साफ दिख रही है। उनका यह भी कहना है कि संगठन के जिन लोगों ने ताला जी को जिताने के लिए दिन-रात मेहनत किया था उन्होंने वैसे सभी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर कर दिया है। यही कारण है कि उनके साथ संगठन का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है।

बोरियो बाजार के राम प्रसाद भगत ने यह बताया कि वर्तमान विधायक और संगठन के बीच तालमेल की कमी साफ-साफ दिख रही है। उनका यह भी कहना है कि संगठन के जिन लोगों ने ताला जी को जिताने के लिए दिन-रात मेहनत किया था उन्होंने वैसे सभी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर कर दिया है। यही कारण है कि उनके साथ संगठन का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है।

भाजपा ने ताला मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संथाल परगना के दिग्गज नेता हेमलाल मुर्मू को छोटा करने का जो प्रयास किया था वह भी विफल हो गया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ताला मरांडी अपने बेटे की शादी के मामले में फंस गए इस किरकिरी के कारण पार्टी ने अपना नुकसान देखते हुए उन्हें पद से हटा दिया। संथाल परगना झामुमो का गढ़ है और उसके किले को भेदने में भाजपा बिल्कुल असफल रही है। अब जबकि महागठबंधन के साथ जेएमएम चुनाव में उतरेगा तो सीधी लड़ाई में भाजपा को सारी ताकत झोंकने पड़ सकती है। बोरियो बाजार के बाद मैं और हमारे साथी ने मंडरो के चुनावी मिजाज को जानने का प्रयास किया।

मंडरो प्रखंड के अधिकांश आदिवासी, संथाल साफ -साफ शब्दों में यह बताने लगे कि वर्तमान विधायक क्षेत्र में कम ही दौरा करते हैं और हम ग्रामीणों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। लोबिन बाबू के समय में जेएमएम के कार्यकर्ता प्रखंड एवं थाना स्तर पर हम लोगों की दिक्कतों को सुनते थे लेकिन अब तो वह भी सुनने वाला कोई नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर क्षेत्र के आदिवासियों की दर्द को बयां करने लगी ,उन्होंने बताया कि ग्रामीण राजनीति में विशेष रूचि नहीं रखते हैं बल्कि सीधे- साधे, भोले -भाले गांव के संथाल सुकून के साथ

गांव के नौजवान थोड़ा सजग हो गए हैं और वह भी अपना भला बुरा समझ कर वोट देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दबंगों की हालत बहुत अच्छी नहीं दिखती। सभी मठाधीश अंदर से घबराए हुए हैं।

दो जून की रोटी मिल जाए, इसी में विश्वास रखते हैं। शिबू सोरेन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए आंगनबाड़ी सेविका ने बताया कि आज आदिवासी समाज में जो भी शिक्षा का प्रभाव दिख रहा है, उसको जगाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन ही थे। जिन्होंने गांव के लोगों को यह बताया कि पढ़-लिख कर ही तुम अपने अधिकार को समझ सकते हो या सरकारी नौकरी में अपने बच्चे को भेजकर अपनी स्थिति सुधार सकते हो। आज जो भी विकास दिख रहा है, उसके पीछे किसी नेता का नहीं बल्कि इस अभियान का असर है। जिसकी शुरुआत शिबू सोरेन ने की थी और दूसरे व्यक्ति लोबिन हेंब्रम हैं, जो लंबे समय से क्षेत्र के नेता रहे हैं और उनका प्रयास सदैव गांव के विकास पर रहा है।

मंडरो प्रखंड के युवा व्यापारी शकील अंसारी अपनी बात कुछ अलग अंदाज में रखते हैं वे कहते हैं कि मंडरो की पहचान भगैया के सिल्क उत्पादन को लेकर पूरे झारखंड में है, बुनकरों की स्थिति बताते-बताते शकील ने यह भी कहा कि यहां के स्थानीय लोग अपनी रोजी-रोटी खुद कमाकर अपना घर चलाते हैं उनको राजनीति से तो कुछ लेना-देना नहीं है, सुकून एवं अमन चैन के चलते यहां के लोग सुखी हैं। आगामी चुनाव के संबंध में जब उनसे हम लोगों ने जानना चाहा तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि साहब हम इलाके के लोग तो सब दिन जेएमएम को ही अपना वोट दिए हैं और आगे भी हम लोग उसी पार्टी को जिताने का प्रयास भी करेंगे लेकिन विगत चुनाव में कुछ वैसे लोग ज्यादा सक्रिय हो गए थे जो क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने के लिए आपसी भाईचारा को खंडित करने का प्रयास कर रहे थे। वह सफल तो नहीं हो सके, लेकिन हो सकता है कि फिर चुनाव में वैसे लोग अपने स्वार्थ के चलते इलाके का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करें।

यहां के स्थानीय लोग अपनी रोजी-रोटी खुद कमाकर अपना घर चलाते हैं। उनको राजनीति से तो कुछ लेना-देना नहीं है। सुकून एवं अमन चैन के चलते यहां के लोग सुखी हैं।

शकील ने यह भी बताया कि वर्तमान विधायक की सक्रियता क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है और विकास की बात तो दूर वह तो लोगों से मिलने भी नहीं आते हैं। उसी चौक पर खड़े एक अन्य नौजवान रोशन मंडल ने शकील के बातों का समर्थन किया और हमारी टीम को बताया कि लोग दैनिक मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं उन्हें पार्टी-पॉलिटिक्स से कुछ लेना-देना नहीं है, चुनाव जब आता है तो पार्टी के लोग गांव के दबंग लोगों के पास आना शुरू करते हैं और उन्हीं को खर्चा - बर्चा देकर चले जाते हैं। गांव के दबंग लोग सीधे-साधे लोगों को जो समझाते हैं लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं और चुनाव के दिन खा-पीकर उनके कहने पर वोट भी दे देते हैं लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदली है।

गांव के नौजवान थोड़ा सजग हो गए हैं और वह भी अपना भला बुरा समझ कर वोट देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दबंगों की हालत बहुत अच्छी नहीं दिखती। यह सभी मठाधीश अंदर से घबराए हुए हैं क्योंकि जब लोबिन हेंब्रम इस क्षेत्र के नेता हुआ करते थे तो गांव के लोग अपनी बात उन तक सीधे पहुंचा देते थे। गांव में जो चर्चा है उससे ऐसा लगता है कि जेएमएम को आगामी चुनाव में फायदा मिल सकता है।

बोरियो विधानसभा का कुछ भाग साहिबगंज के शहरी इलाके में भी आता है। वैसे तो शहर के लोग राजनीति पर खुलकर अपना विचार नहीं देते हैं लेकिन दबी जुबान से वह भी यह मानते हैं कि जेएमएम का प्रभाव सदैव ही इस विधानसभा पर रहा है। पूर्व विधायक के प्रति कोई खास नाराजगी भी नहीं दिख रही। शहरी इलाके में ज्यादातर मतदाता हिंदू और मुस्लिम हैं, यहां आदिवासी की संख्या नगण्य है फिर भी दोनों समुदाय के लोग यह मानते हैं कि लोबिन बाबू अच्छे नेता हैं और जब भी लोग उनसे मिलने जाते हैं उनसे बढ़िया से मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। यही पहचान उनकी ताकत भी है। सरकारी कर्मचारी भी भाजपा के खिलाफ अपना विचार खुलकर रख रहे थे और यह बताने लगे कि रिजर्व सीट का कोई भी नेता ज्यादा सक्रिय तो नहीं दिखता है, बावजूद इसके लोबिन बाबू हम लोगों के ज्यादा करीब हैं। कुछ लोग ताला मरांडी और भाजपा दोनों के पक्ष में अपना विचार इस रूप में व्यक्त कर रहे थे कि हम लोग पार्टी लाइन पर अपना वोट देते हैं ना कि व्यक्ति विशेष को देखकर।

देवघर-दुमका के क्षितिज पर चमक रहीं रीता चौरसिया

गांव में रोजगार की कमी है आज भी हजारों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने रहे हैं। उनके लिए काम करने की जरुरत है। शहर के लोग तो कुछ न कुछ रोजगार कर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन गांवों की स्थिति खराब है। इस पर फोकस कर रही भाजपा नेत्री ने **राजनीति गुरु** से विस्तार से बात की।

रीता चौरसिया आज देवघर व दुमका जिले की राजनीति में एक सशक्त राजनीतिक महिला नेत्री के रूप में उभर रही हैं। देवघर नगर निगम गठन के बाद वार्ड संख्या एक की पहली वार्ड पार्षद के रूप में चुनी गईं रीता चौरसिया ने अपने वार्ड में अभूतपूर्व और कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर वार्ड की जनता की चहेती बनीं और दूसरी बार निर्विरोध वार्ड पार्षद चुनी गईं। रीता चौरसिया अपने वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहती हैं। पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव जीतने के बाद ही भाजपा की सक्रिय राजनीति से जुड़ीं और भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, जिसके बाद प्रदेश संगठन ने उन्हें प्रदेश कार्यसमिति में स्थान दिया है।

रीता चौरसिया को समाजसेवा विरासत में मिली है, उनके पूर्वजों का समाजसेवा से गहरा संबंध रहा है। उनके ससुर डॉ छोटेलाल मोदी स्वतंत्रता सेनानी थे और पिता डॉ रामलखन प्रसाद समाजसेवी, पति डॉ आर के चौरसिया शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। चिकित्सा जगत में उनके पुत्र डॉ राहुल चौरसिया व पुत्रवधु डॉ स्मारिका भी मरीजों की सेवा कर रही हैं। सारी सुख- सुविधाओं को त्याग कर रीता चौरसिया ने समाजसेवा को इसलिए चुना कि उनकी कोशिशों से यदि कुछ लोगों का भला हो जाए तो बड़ी बात होगी। इसलिए शायद ही किसी दिन वह अपने आवास पर आराम करती हैं।

आधे दर्जन से अधिक देशों का भ्रमण कर वहां की जनसुविधाओं पर गहरा मंथन एवं जानकारी प्राप्त चुकी रीता चौरसिया सुबह से ही आमजनता की समस्याओं के निदान पर ध्यान लगाने के बाद दोपहर से पहले जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं से रूबरू होती हैं। रीता चौरसिया कहती हैं कि शहरी क्षेत्रों के लोगों में रोजगार की संभावनाएं रहती है, लोग कुछ न कुछ रोजगार एवं व्यवसाय कर जीवनयापन में काफी सुधार ला रहे है लेकिन सुदूर गांव के भोले- भाले ग्रामीण पुरूष व महिलाएं आज भी काफी दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। या तो थोड़ी बहुत खेती कर या परंपरागत छोटे व्यवसायों से किसी तरह दो जून रोटी का इंतजाम कर पा रहे हैं।

बच्चों की शिक्षा का मामला हो या महिलाओं के समुचित स्वास्थ्य की देखभाल। रीता चौरसिया कहती हैं कि आज भी गांवों में कर्मठ और लगन से काम करने वाले लोग हैं लेकिन आय के अच्छे स्त्रोत नहीं हैं, जो आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार की ओर से कई जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं परन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा और बिचौलियों की दखल है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। वो कहती हैं कि इसके लिए सरकारी पदाधिकारियों के सार्थक प्रयासों साथ सामानांतर रूप से ग्रामीणों को प्रोत्साहित व जागरूक करना जरूरी है। वो कहती हैं कि ग्रामीणों की शिकायत है कि सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक कर प्रयास ही बंद कर देते हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करना और डोर-टू-डोर योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों की दूरी पाटना आवश्यक है, तभी सरकार के प्रयासों को धरातल पर उतारा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का गांवों का सर्वांगीण विकास व डिजीटल भारत का सपना पूरा हो सकेगा। रीता चौरसिया कहती हैं कि आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में दमदार उपस्थिति दर्ज कर जनता के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि के रूप में ही इस महती अभियान में सफल हो सकते हैं। वे बताती हैं कि अबतक सौ से अधिक गांवों के अंदर जाकर महिलाओं व बच्चों के विकास के साथ बुनियादी सुविधा का जल्द लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत कर रही हैं। आज देवघर एवं दुमका जिले में भारतीय जनता पार्टी के सशक्त राजनीतिक महिला नेत्री के रूप में दमदार उपस्थिति दर्ज कर चुकी रीता चौरसिया मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ से लेकर सभी मंत्री, सांसद, विधायक के बीच अपना अलग पहचान भी बना चुकी हैं। किसी भी सरकारी व भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। अत्यंत ही सरल व मृदुभाषी स्वाभाव की होने के कारण जिले के उपायुक्त हों या पुलिस अधीक्षक या अन्य पदाधिकारीगण सभी से उनका गहरा सद्भावपूर्ण संबंध रहा है। रीता चौरसिया कहती हैं, प्रदेश नेतृत्व के साथ जनता का आशीर्वाद मिला तो उन जरूरतमंदों की सेवा कर अपने को भाग्यशाली खुद को समझूंगी।

आज भी गांवों में कर्मठ और लगन से काम करने वाले लोग हैं लेकिन आय के अच्छे स्त्रोत नहीं हैं, जो आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार की ओर से कई जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं परन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

रतन कुमार

बिहार में भूमिपुत्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी पार्टी : कौशलेंद्र

शिव सेना के बिहार राज्य प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा ने कहा है कि आज देश के हर क्षेत्र में बिहारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। शायद देश के लोग बिहार की गौरवशाली इतिहास को भूल गए हैं। यह वही बिहार की धरती है जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। बड़े ही दुखद बात है कि आज उसी मिट्टी के लोगों को अपने ही देश में तिरस्कार की भावना से देखा जाता है। कौशलेंद्र शर्मा ने कहा कि अब किसी भी सूरत में बिहारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बिहार के तमाम राजनीतिक दलों , विधायकों और सांसदों से अपील की है कि बिहारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करने वालों का कड़ा विरोध करें। इस मुद्दे पर सभी एक हों। इस पर राजनीति न करें। कौशलेंद्र ने कहा कि बिहार में पैदा होना कोई पाप नहीं , बल्कि गर्व की बात है। आज बिहार के विद्यार्थी देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना बिहार के हर भूमिपुत्र की लड़ाई लड़ेगा। प्रत्येक आदमी को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष करेगा, जिसका वह हकदार है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वहां के भूमिपुत्र को रोजगार ,शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था सरकार से लड़कर दिलवाई गई है। उसी प्रकार बिहार में भी शिवसेना बिहारी भूमिपुत्र की लड़ाई लड़ेगी। बौद्ध ,जैन, सिख धर्म के संतों की धरती बिहार को पिछड़ा ,कमजोर

किसी भी सूरत में बिहारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौशलेंद्र ने बिहार के तमाम राजनीतिक दलों , विधायकों और सांसदों से अपील की है कि बिहारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करनेवालों का कड़ा विरोध करें।

,गरीब बताकर दूसरी पार्टियां हमें शर्मिंदा करती हैं। कौशलेंद्र ने कहा कि जिस बिहार की भूमि इतनी उपजाऊ, जहां पानी की प्रचुरता है। जिसने बिहार को पिछड़ा बनाया उन सभी राजनीतिक पार्टियों एवं सरकारों की कुर्सी हिलानी होगी। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर राजनीति करती हैं। चुनाव के समय बड़े-बड़े सुहाने सपने दिखाए जाते हैं और जैसे ही उनका अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है वह चुनाव में किए गए सारे वादे भूल जाते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल किया कि जब आप जाति की ही राजनीति करते हैं तो फिर उस जाति के लोगों का विकास क्यों नहीं करते। आखिर कब तक दलित , महादलित , ओबीसी आदि के नाम पर चुनाव जीतते रहेंगे । कौशलेंद्र ने कहा कि समय आ गया है कि आम जनता इन स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं का बहिष्कार करें । तभी समाज में बदलाव होगा। इसके लिए पढे-लिखे लोगों को राजनीति में आना होगा। देश के युवा पीढ़ी को राजनीति की बागडोर अपने हाथों में लेना होगा। आम जनता को स्वच्छ राजनीति के बारे में जागरुक करना होगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ सराहनीय काम जरूर किए हैं। लेकिन 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना बिहार का विकास कर सकते थे उतना नहीं हुआ। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में टॉपर घोटाला को लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिहार का नाम खराब हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री को सुधार करना होगा। बिहार में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थीं। जो अब तक नहीं लगी। जिसके कारण यहां के बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं।

तैलिक समाज के नायक हैं रघुवर दास

उमेश रंजन साहू

मेरी नजर में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी तैलिक साहू समाज के मसीहा हैं। उन्हें समाज को लेकर चिंता है। वह चाहते हैं कि समाज के नौजवान शिक्षित हों और देश को दिशा दें।

झारखंड का वैश्य और तेली समाज मुख्यमंत्री रघुवर दास को अपने सम्मान से जोड़कर देखता है। तैलिक समाज को लगता है कि पहली बार उनके समाज के किसी शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, इसलिए कुछ लोगों के विरोध के बाद भी झारखंड का तेली समाज पूरी तरह रघुवर दास जी को अपना नायक मानता है और उन पर गर्व करता है।

पिछले दिनों दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय तैलिक समाज का विशाल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आए थे। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा भी कि वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आए हैं, समाज के एक व्यक्ति के रूप में आए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इतिहास बताता है कि तैलिक साहू समाज ने पहले भी सत्ता चलाई है। यह समाज पूरी तरह भाजपा के साथ है।

हाल में गोमिया उपचुनाव के दौरान कुछ लोग झामुमो के बहकावे में आ गए थे, लेकिन बाद में उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री जी समाज के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए समर्पित हैं और समाज हमेशा उनके पीछे खड़ा है।

झारखंड में तैलिक साहू समाज, वैश्य समाज की बड़ी आबादी है। 12 सीटों पर हार जीत का फैसला यही समाज करता है और अगले चुनाव में हमारे समाज के सारे लोग गोलबंद होकर भाजपा को समर्थन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से समाज का सम्मान बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारे समाज की विशाल आबादी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाज को प्रदान करेंगे। ऐसे में पूरी तरह एकजुट होकर यह समाज भाजपा को मजबूत करने में अपनी शक्ति लगाएगा। अभी वैश्य और तैलिक साहू समाज की राजनीतिक नुमाइंदगी बहुत कम है। हमारे समाज से एक भी मंत्री नहीं है, विधायक भी बहुत कम है, इसलिए भाजपा को और मुख्यमंत्री जी को समाज के न्यायोचित मांग पर विचार करना चाहिए।

तैलिक साहू समाज, वैश्य समाज की बड़ी आबादी है। 12 सीटों पर हार जीत का फैसला यही समाज करता है।

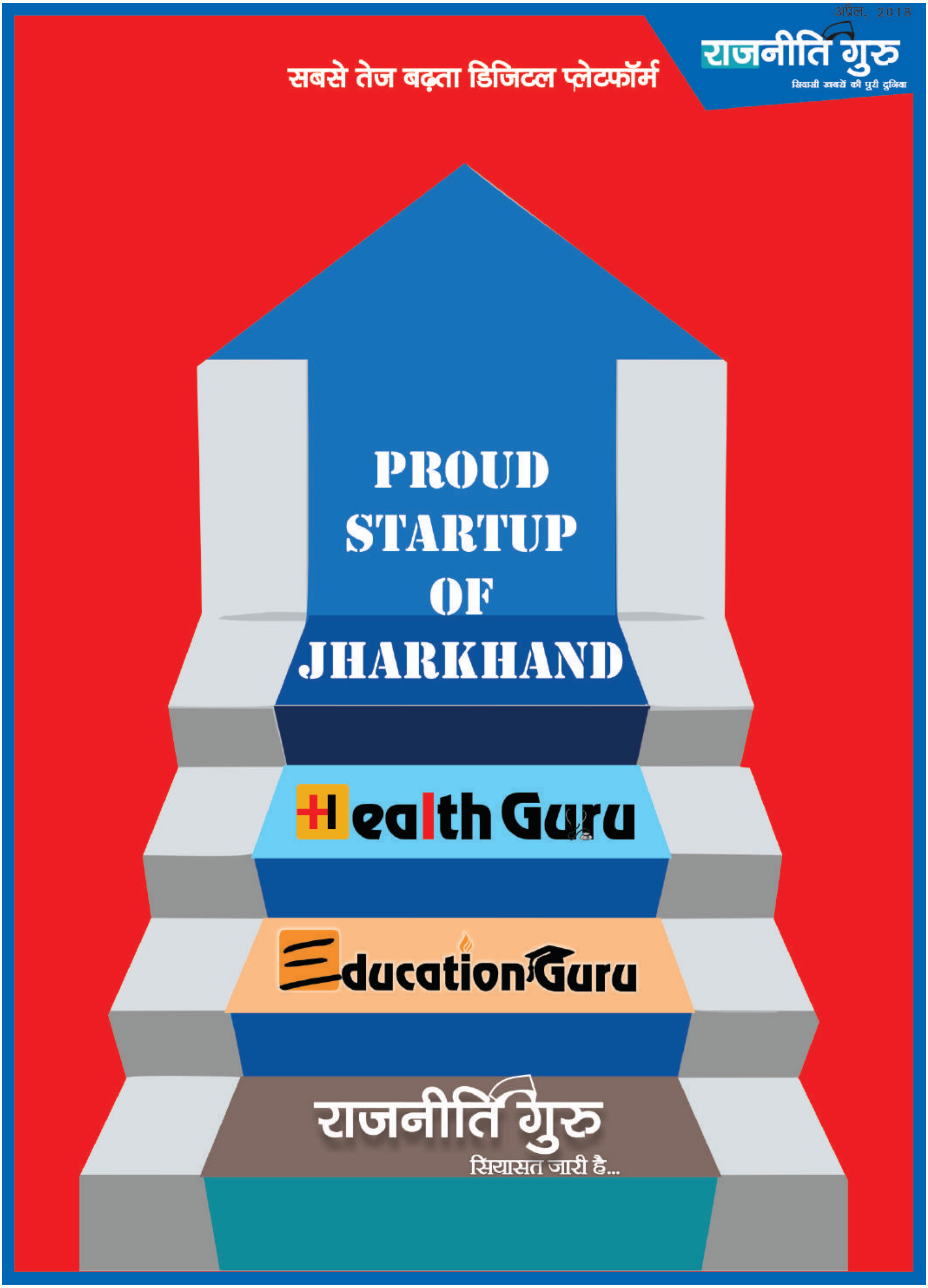

राजनीति गुरु
सियासी खबरों की पूरी दुनिया
सबसे तेज बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म
PROUD
STARTUP
OF
JHARKHAND
Health Guru
Education Guru
राजनीति गुरु
सियासत जारी है...

मजबूत कल के लिए बेहतर कॉलेज

K. S. G. M. College

(Affiliated to Vinoba Bhave University, Hazaribagh)
Nirsa, Dhanbad

"अच्छे व अनुभवी शिक्षकों के प्रयासों तथा कैंपस में अनुशासन की वजह से हमारे कॉलेज का रिजल्ट हर साल बेहतर हो रहा है। इस इलाके की छात्राओं के लिए यह महाविद्यालय वरदान साबित हो रहा है"

– कुंज बिहारी भट्ट, प्राचार्य

- बेहतरीन, सुरक्षित और सुगम कैंपस
- विज्ञान, कला और वाणिज्य में स्नातक स्तर की पढ़ाई
- अनुभवी और योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा
- व्यक्तित्व निर्माण के लिए खेल-कूद की अच्छी व्यवस्था